



भारत-साइप्रस के बीच द्विपक्षीय वार्ता

समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंध : पीएम मोदी

नई दिल्ली। भारत और साइप्रस के संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिल्डेस के बीच नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती न केवल मजबूत है, बल्कि भविष्य की ज़रूरतों और संभावनाओं के अनुरूप भी है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्री समेत दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध समय की कसौटी पर बार-बार खरे उतरे हैं और अब इन्हें नई दिशा देने के लिए रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिल्डेस और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हुए कहा कि पिछले वर्ष साइप्रस यात्रा के दौरान उन्हें मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और सम्मान को भारत कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि साइप्रस द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रति सम्मान और दोनों देशों के गहरे रिश्तों का प्रतीक है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस की साझेदारी लोकतंत्र, कानून के शासन और संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत हमेशा इन सिद्धांतों के प्रति



पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हुआ है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (सझ) के चलते कई नई आर्थिक संभावनाएं खुली हैं और भारत अगले पांच वर्षों में इस निवेश को फिर से दोगुना करने का लक्ष्य रखता है।

उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, भारत शांति और संघर्षों के जल्द समाधान के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। साथ ही उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार को ज़रूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत-साइप्रस रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा, नई महत्वाकांक्षा और नई गति लेकर आएगी।

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिल्डेस ने कहा कि उनका मुख्य फोकस भारत और साइप्रस के द्विपक्षीय संबंधों को

मजबूत करने के साथ-साथ भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर है।

भारत की तीन दिन की यात्रा पर आये साइप्रस के राष्ट्रपति महामहिम निकोस क्रिस्टोडूलाइड्स के साथ शुक्रवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच जिन छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए उनमें आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह की स्थापना, वर्ष 2026-2031 के लिए रक्षा सहयोग रोडमैप, साइप्रस के अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल नीति उप मंत्रालय तथा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी समझौता शामिल है। भारत और साइप्रस ने साइबर सुरक्षा संवाद और कांसुलर संवाद शुरू करने पर भी सहमति जताई, जबकि साइप्रस के लारनाका संयुक्त बचाव समन्वय केंद्र और भारत के रक्षा मंत्रालय के बीच खोज एवं बचाव सहयोग को लेकर तकनीकी व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किये गये।

लापता बच्चों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सभी राज्यों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाने का आदेश

नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रहे लापता बच्चों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने चिंता जताते हुए कहा कि इस समय देशभर में करीब 47 हजार बच्चे अब भी लापता हैं और इनमें से कई मामलों के पीछे संगठित मानव तस्करी गिरोहों की भूमिका हो सकती है।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र और राज्यों को कई अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति, खासकर बच्चे के लापता होने की जानकारी मिलते ही पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी। इसके लिए प्रारंभिक जांच का

इंतजार नहीं किया जाएगा और न ही इसे केवल परिवार की शिकायत पर निर्भर छोड़ा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपहरण और मानव तस्करी से जुड़ी धाराएं अनिवार्य रूप से लगाई जानी चाहिए। अदालत का मानना है कि अगर शुरुआत से ही मामले को गंभीर अपराध मानकर जांच की जाएगी तो बच्चों की जल्द तलाशने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि अदालत ने यह भी कहा कि जब कोई बच्चा लापता होता है तो पुलिस और प्रशासन को पहले ही यह मानकर कार्रवाई करनी चाहिए कि मामला अपहरण या तस्करी से जुड़ा हो सकता है। इससे जांच में देरी नहीं होगी

और अपराधियों पर जल्द कार्रवाई संभव हो सकेगी।

मौजूद जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को भी बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि देश के सभी पुलिस थानों को एक साझा डिजिटल मंच से जोड़ा जाए, जहां मानव तस्करी, महिलाओं और बच्चों की गुप्तशुद्धी से जुड़ा विशेष पोर्टल उपलब्ध हो। इससे अलग-अलग राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय बेहतर हो सकेगा।

अदालत ने मानव तस्करी निरोधक इकाइयों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को अगले चार सप्ताह के भीतर पूरी तरह

सक्रिय और कार्यशील बनाया जाए।

इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि जिन बच्चों को बरामद किया जाता है, उन्हें सामान्य परिस्थितियों में 24 घंटे के भीतर परिवार को सौंप दिया जाना चाहिए। हालांकि अगर परिवार पर ही तस्करी या शोषण में शामिल होने का शक हो तो अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार सत्यापन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि किसी भी बरामद व्यक्ति या बच्चे का तुरंत आधार सत्यापन कराया जाए या उसका आधार कार्ड बनवाया जाए, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट जैसी जानकारी दर्ज होती है।

भीषण गर्मी का कहर पारा 48 डिग्री के पार



नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने इस सप्ताह भीषण लू की स्थिति को देखते हुए उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के साथ-साथ पूर्वी भारत के आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की स्वास्थ्य सलाह में गुरुवार को चेतावनी दी गई कि लू की स्थिति से गर्मी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसमें किसानों से फसलों की सुरक्षा

के लिए हल्की और नियमित सिंचाई करने का भी आग्रह किया गया है।

उत्तर प्रदेश का बांदा शहर इस मौसम का सबसे गर्म क्षेत्र रहा है, जहां पिछले दो दिनों में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं, दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 14 साल का सबसे गर्म रात का रिकॉर्ड है। ओडिशा, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, बिहार, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात का तापमान सामान्य से 3.1°C से 5°C अधिक दर्ज किया गया है। देश के उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों के अन्य क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से 1.6 °C से 3.0 °C अधिक रहा। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान वर्तमान में 40 से 47°C के बीच है।



रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बलौदाबाजार जिले के करहीबाजार में आयोजित सुशासन तिहार समाधान तिथि में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं और सेवाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में मुख्यमंत्री ने 65 व्षीय श्रीमती अनुपकुंवर पाल तथा कक्षा छठवीं के छात्र संजय चक्रधारी एवं जयसेन को अपने हाथों से नजर का चश्मा पहनाया।

54 प्रशिक्षु सूबेदारों की जिलों में होगी तैनाती

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने राज्य पुलिस सेवा के 54 प्रशिक्षु सूबेदारों को जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न जिलों में पदस्थ किया है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इन प्रशिक्षु सूबेदारों को प्रदेश के अलग-अलग पुलिस जिलों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। इनमें राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, भमतरी, रायगढ़, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जशपुर, पूरजपुर, नायागपुर, बलौदाबाजार, कोरिया और रायपुर सहित कई जिले शामिल हैं।इनकी तैनाती का उद्देश्य फ़ोल्ड स्तर पर पुलिसिंग की व्यावहारिक समझ विकसित करना और कानून-व्यवस्था की वास्तविक स्थिति से परिचित कराना है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु सूबेदार संबंधित जिलों में पुलिसिंग कार्यों, जांच प्रक्रिया और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को सीखेंगे। पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह प्रशिक्षण व्यवस्था पुलिस सेवा में दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है, जिससे भविष्य में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित की जा सके।

प्रमुख समाचार

10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को वोटिंग

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान 18 जून को होगा और परिणाम उसी दिन शाम 5 बजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 10 राज्यों में होगा, जहां मौजूदा सांसदों का कार्यकाल अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। ये चुनाव 21 जून से शुरू होकर 19 जुलाई को समाप्त होंगे। राज्यसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में चार-चार सीटों पर; मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन सीटों पर; झारखंड में दो सीटों पर; और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक-एक सीट पर होगा। राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने वालों में एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन ; कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल सहित अन्य शामिल हैं। अन्य सेवानिवृत्त सदस्यों में अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी, पिछ्छी सुभाष चंद्र बोस, और परिमल नाथवानी शामिल हैं।

बिहार में सुशासन से कोई समझौता नहीं : सम्राट चौधरी

पटना। बिहार में पुलिस मुठभेड़ों को लेकर राजनीति तब और तेज हो गई जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर राज्य में हाल ही में अपराधियों के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई से संबंधित आरोपों को लेकर पलटवार किया और उनकी टिप्पणियों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अब कह रहे हैं कि अगर पुलिस मुठभेड़ होती है, तो पुलिस को पहले अपराधी की जाति पछनी चाहिए। मैं पुलिसकर्मियों से कहूंगा- ठीक है, पहले उनकी जाति पूछो और फिर गोली चलाओ। उन्होंने पटना में पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने पुलिस को खुली छूट दी है। राज्य में 'सुशासन' बनाए रखना सरकार की प्रतिबद्धता है। सुशासन पर कोई समझौता नहीं होगा। राज्य में कानून का राज कायम है। अगर कोई पुलिस को चुनौती देने की हिम्मत करता है, तो उसे 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे आरोप बिल्कुल निराधार हैं। हम सुशासन में विश्वास रखते हैं।

नीट पेपर लीक मामले में पीएम और मंत्री प्रधान जवाबदेह

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि नीट-यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक और इसे दबाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उरमेश ने नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रश्नपत्र लीक माफिया के साथ मिलकर सच्चाई को दबाने का भी आरोप लगाया। उनकी यह टिप्पणी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के उन बयानों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने संसदीय स्थायी समिति को बताया था कि नीट-यूजी 2026 परीक्षा का प्रश्नपत्र पूरी तरह से लीक नहीं हुआ था, बल्कि परीक्षा से पहले केवल कुछ प्रश्न ही सामने आए थे। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 2018 में एनटीए के गठन के बाद से, मोदी सरकार और उसका तंत्र एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में व्यास अनियमितताओं और धोखाधड़ी की सच्चाई को दबाने के लिए प्रश्नपत्र लीक माफिया के साथ मिलीभगत कर रहा है।

आईआरसीटीसी घोटाले में फिटरला फैसला, 9 जून को सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला शुक्रवार को 9 जून तक के लिए टाल दिया। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है और यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए एक मूल अपराध पर आधारित है। ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच आईआरसीटीसी होटलों के संचालन के ठेके देने में अनियमितताएं हुईं। एजेंसी के अनुसार, होटल रखरखाव के ठेके कथित तौर पर निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना एक निजी कंपनी को दिए गए थे। बताया जाता है कि यह कंपनी आरजेडी प्रमुख के करीबी सहयोगियों से जुड़ी हुई थी।

अमित शाह ने शुभेंदु को बताया कैबिनेट विस्तार का फार्मूला

नई दिल्ली। बंगाल में नई सरकार बने दो सप्ताह हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 14 दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि, राज्य में मंत्रिमंडल गठन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केवल 5 मंत्रियों को ही विभाग आवंटित किए गए हैं। पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कब होगा और किसे कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, इस पर अटकलें लगाई जा रही थीं। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की दिल्ली यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के साथ बंगाल में मंत्रिमंडल गठन पर विस्तृत चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, बंगाल में जल्द ही पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। मंत्रिमंडल के गठन के साथ-साथ सीमा पर कटेदार तार लगाने और सीएए के कार्यान्वयन पर भी चर्चा हुई। मंत्रिमंडल में किस योग्यता के आधार पर लोगों को स्थान दिया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है।

यूपी में हैट्रिक की तैयारी में भाजपा, संगठन में बड़े बदलाव तय

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल तेज हो गई है। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, पर अभी तक अपनी टीम का गठन नहीं कर सके हैं। यूपी में बीजेपी के सामने सत्ता की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो जातीय और क्षेत्रीय बैलेंस बनाने का चैलेंज है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। योगी कैबिनेट विस्तार के बाद अब यूपी बीजेपी संगठन की बारी है। सूबे में संगठन की कमान संभाल रहे पंकज चौधरी की टीम का खाका तैयार हो गया

है। प्रदेश की कार्यकारिणी से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों तक कई अहम पदों पर फेरबदल की तैयार कर ली गई है। पंकज चौधरी की टीम में कई नए और युवा चेहरों को मौका देने की प्लानिंग है, जबकि लंबे समय से संगठन में सक्रिय अनुभवी नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी या केंद्रीय जिम्मेदारियों में भेजे जाने की रणनीति है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे। यह बैठक यूपी संगठन और मिशन-2027 को लेकर हुई। बीजेपी ने सरकार

से लेकर संगठन तक को सियासी धार देना शुरू कर दिया है, ताकि सत्ता की हैट्रिक लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की कमान पंकज चौधरी को मिले हुए छह महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के बीच कई दौर की बैठकों में संगठनात्मक ढांचे को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा कोर कमेटी की बैठकों में राय-मशविरा किया जा चुका है। 2027 को लेकर हुई। बीजेपी ने सरकार



की बैठक के बाद प्रदेश की नई कार्यकारिणी का खाका लगभग तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, पंकज चौधरी, बीएल संतोष और धर्मपाल के बीच बुधवार को दो घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में

जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की यूपी संगठन को लेकर आज फिर से बैठक होगी है। सूत्रों की मानें तो बुधवार को हुई बैठक में नई टीम के नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई, जिस पर 22 मई मंथन किया जाएगा। बीजेपी नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी नई टीम और नई ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं की मौजूदगी में हुए मंथन में इस पर विशेष चर्चा हुई। यूपी पंकज चौधरी

की टीम जगह दिए जाने वाले चेहरों पर विचार की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जिला से लेकर प्रदेश के अहम पदों पर बैठाया जा सकता है। वहीं, नितिन नवीन की टीम में यूपी के कुछ नेताओं को जगह मिल सकती है। इस कारण प्रदेश स्तर पर भी जगह खाली होने की उम्मीद की जा रही है। योगी सरकार में 6 नए मंत्रियों को शामिल किए जाने के बाद संगठन में बदलाव कर बीजेपी पूरी मजबूती और समीकरणों को साधकर चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रही है। बीजेपी ने ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारी देने की योजना बनाई है, जो

लंबे समय से संगठन में सक्रिय और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं कई अनुभवी पदाधिकारियों की भूमिका बदली जा सकती है। भाजपा आगामी चुनावी रणनीति को देखते हुए संगठन में संतुलन और ताजगी लाने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बनाई जाएगी, उसमें जातीय संतुलन को भी देखा जाएगा। इसके साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान रखे जाने की बात कही जा रही है। प्रदेश कार्यकारिणी में जातिगत पैमाने के साथ-साथ सांगठनिक अनुभव को अहमियत देने की भी योजना बनाई रही है।

जन चौपाल में जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं

बीजापुर। बीजापुर के सुदूर गांवों सागमेटा, सण्ड्रा, एडापल्ली और पीलूर पहुंचकर कलेक्टर विश्वदीप, एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव और सीईओ नम्रता चौबे ने जन चौपाल लगाई तथा ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। कलेक्टर ने सण्ड्रा में युवाओं के साथ क्रिकेट खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया और शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जिले के सुदूर और संवेदनशील ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की सक्रिय मौजूदगी ने एक बार फिर ग्रामीणों में भरोसे और उत्साह का माहौल पैदा किया। कलेक्टर विश्वदीप, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव और जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे ने ग्राम पंचायत सागमेटा, सण्ड्रा, एडापल्ली और पीलूर पहुंचकर जन चौपाल लगाई

युवाओं संग क्रिकेट खेल कलेक्टर ने जीता ग्रामीणों का दिल



तथा ग्रामीणों की समस्याएं जमीन पर बैठकर गंभीरता से सुनीं।अधिकारियों के गांव पहुंचने से ग्रामीणों ने प्रशासन को अपने बीच महसूस किया और खुलकर अपनी समस्याएं एवं सुझाव साझा किए। जन चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण, राशन वितरण, पेयजल संकट, स्वास्थ्य सुविधाएं,

शिक्षा, आवागमन और अन्य मूलभूत जरूरतों से जुड़े मुद्दे उठाए। कलेक्टर विश्वदीप ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की मंशा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले

लोगों को किसी भी सुविधा के लिए भटकना न पड़े। कलेक्टर ने बस्तर मुन्ने कार्यक्रम के शत-प्रतिशत संचुरेशन पर विशेष जोर देते हुए पात्र ग्रामीणों को जरूरी दस्तावेज सरलता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर बल दिया। दौरे के दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र में चल रहे जनगणना कार्य की भी समीक्षा की और ग्रामीणों को इसके महत्व से अवगत कराया। ग्रामीणों से जनगणना में सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए अधिकारियों ने कहा कि सही आंकड़े ही विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का आधार बनते हैं। पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने ग्रामीणों से संवाद कर सुरक्षा,

सामाजिक सहभागिता और आपसी विश्वास को मजबूत बनाने की बात कही। वहीं जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे ने पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों में समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और गति बनाए रखने के निर्देश दिए।

इस दौरे का सबसे प्रेरणादायक दृश्य ग्राम सण्ड्रा में देखने को मिला, जब कलेक्टर विश्वदीप गांव के युवाओं के साथ क्रिकेट मैदान में उतरे। कलेक्टर ने युवाओं के साथ क्रिकेट खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें खेल, शिक्षा तथा सकारात्मक सोच के जरिए जिले के विकास में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बीजापुर के विकास और सकारात्मक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत यहां के युवा हैं।

राहुद में सुशासन तिहार पर 1428 आवेदनों का किया गया निराकरण



बालोद। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम राहुद में गुरुवार को शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत राहुद सहित राहुद कलेस्टर में शामिल आसपास के 18 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इसके अंतर्गत गुण्डरदेही विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती

तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर, पूर्व विधायक श्री वीरेन्द्र साहू, जनपद अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर, जनपद उपाध्यक्ष श्री नोतेश मोठी यादव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कांति सोनेश्वर सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर हितग्राहियों को कृषि विभाग अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मत्स्य पालन प्रसार योजना अंतर्गत जाल एवं आईस बॉक्स का वितरण किया गया। इसी तरह समाज कल्याण विभाग अंतर्गत श्रवण यंत्र एवं छड़ी,

स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेख पत्र का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र एवं केसीसी कार्ड का वितरण किया। इसके अलावा शिविर में राज्य शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने हेतु मेडिकल बोर्ड लगाया गया था। इस दौरान मेडिकल बोर्ड में शामिल विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा शिविर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने पहुंचे दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी बनाया गया। शिविर में अतिथियों के द्वारा नन्हें-मुन्हें बच्चों को स्पाइडर खीर खिलाकर उनका अन्नप्राशन संस्कार कराया गया।

तेंदूपत्ता से भरे दो ट्रकों में लगी भीषण आग लाखों का माल जलकर खाक



कवर्धा/कांकेर। छत्तीसगढ़ के दो अलग-अलग जिलों में तेंदूपत्ता परिवहन कर रहे ट्रकों में भीषण आग लग गई। कवर्धा और कांकेर जिलों में हुए इन हादसों में लाखों रुपये का तेंदूपत्ता और दोनों ट्रक जलकर पूरी तरह खाक हो गए हैं। राहत की बात यह रही कि दोनों ही घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। दोनों घटनाओं का वीडियो भी सामने आया है। कवर्धा जिले के बोड़ला थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। नगर पंचायत बोड़ला के दैहान के पास तेंदूपत्ता से भरा एक आईसर ट्रक अचानक ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया। तार टकराते ही ट्रक में जोरदार स्मॉकिंग हुई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरा वाहन धू-धू कर जलने लगा और उसमें भरा भारी मात्रा में तेंदूपत्ता राख के ढेर में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि यह ट्रक भोंदा कला से तेंदूपत्ता लोड करके बोड़ला

गोदाम की ओर जा रहा था। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही बोड़ला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी घटना कांकेर जिले से सामने आई है, जहां तेंदूपत्ता से भरे एक अन्य ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में भी लाखों रुपये का तेंदूपत्ता और ट्रक जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार, जलकर खाक हुआ तेंदूपत्ता सोनपुर समिति का था। ट्रक कोयलीबेड़ा के रास्ते होकर नारायणपुर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। घटना की जानकारी मिलते ही कोयलीबेड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

घेराबंदी देख पुलिसवालों को किया कुचलने का प्रयास, फिर खुद हो गए हादसे का शिकार



गरियाबंद। जिले की देवभोग पुलिस ने फिल्मी अंदाज में घेराबंदी कर दो स्विफ्ट कारों से करीब 75 लाख रुपये कीमत का डेढ़ क्रिंटल गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े जाने के डर से तस्करों ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। मिली

जानकारी के अनुसार, तस्करों ने ओडिशा से गांजा भरने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी गाड़ियों की मध्य प्रदेश (स्कू) की नंबर प्लेट निकालकर

छत्तीसगढ़ (एत) की नंबर प्लेट लगा दी थी, लेकिन देवभोग पुलिस को इसकी पुछा सूचना पहले ही मिल चुकी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तत्काल

नाकाबंदी की। थाना प्रभारी फैजुल हुदा शाह ने बताया कि नाकाबंदी देखकर आरोपियों को भनक लग गई और उन्होंने भागने की कोशिश की। इस दौरान रोकने का प्रयास कर रहे पुलिसकर्मियों के ऊपर ही तस्करों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा करने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई। पुलिस से बचने के लिए तेज रफ्तार में भाग रही तस्करों की दोनों स्विफ्ट कारें

अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर पांचों को हिरासत में ले लिया। कारों की तलाशी लेने पर उसमें से डेढ़ क्रिंटल गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 75 लाख रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी मध्य प्रदेश के गांधी नगर और साजनाबाद जिले के रहने वाले हैं। पकड़े गए तस्करों में एक नाबालिग है, जबकि अन्य 4 आरोपियों की उम्र

22 से 26 साल के बीच है। पुछताछ में आरोपियों ने कबुला कि वे हमेशा की तरह इस बार भी एक बड़े नेटवर्क के इशारे पर मोटी मजदूरी के चक्कर में गांजा सप्लाई करने जा रहे थे। देवभोग पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (बृहत्) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। बता दें कि देवभोग पुलिस की गांजा तस्करी के खिलाफ यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है।

रामानुजगंज में मिलीं 96 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि

बलरामपुर-रामानुजगंज। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देशभर में चलाए जा रहे पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के तहत बलरामपुर जिले से लगातार महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की जानकारी सामने आ रही है। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में लोग खुद आगे आकर अपने पास सुरक्षित पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों की जानकारी प्रशासन को दे रहे हैं। प्रशिक्षित सर्वेयर इन दस्तावेजों का दस्तावेजीकरण कर उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। इसी कड़ी में रामानुजगंज के मध्य बाजार निवासी रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के परिवार के पास करीब 96 साल पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि सुरक्षित मिली है। यह पांडुलिपि उनके पूर्वज लक्ष्मी प्रसाद रौनियार ने वर्ष 1930 और उसके बाद अलग-अलग वर्षों में देवनागरी हिंदी में लिखी थी। इस दुर्लभ पांडुलिपि को देखने बलरामपुर जिले के नोडल अधिकारी रामपथ यादव, सहायक नोडल संजय कुमार गुप्ता और जिला ग्रंथपाल राजकुमार शर्मा गुप्ता परिवार के घर पहुंचे।

151 गुम मोबाइल मालिकों को लौटाए, लोगों के चेहरे खिले

धमतरी। धमतरी पुलिस के एक विशेष अभियान की सफलता से लोगों के चेहरे खिल उठे। पुलिस 151 गुम मोबाइल खोजकर उसके असली मालिकों को लौटाएं हैं। पुलिस ने बताया कि बरामद सभी मोबाइल की कीमत 22 लाख रुपये है। इन मोबाइलों को छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश, उड़ीसा समेत विभिन्न राज्यों से ट्रेस कर रिकवर किया गया। मोबाइल वितरण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन रूढ़ी स्थित पुलिस कंपोजिट बिल्डिंग में किया गया, जहां जिलेभर से पहुंचे हितग्राहियों को उनके गुम मोबाइल लौटाए गए। कार्यक्रम में कलेक्टर अंबिनाश मिश्रा, महापौर रामू रोहरा एवं पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार विशेष रूप से मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि धमतरी पुलिस का यह अभियान सफल हुआ है। अधिकारियों ने हितग्राहियों को मोबाइल सौंपते हुए पुलिस की तकनीकी टीम और साइबर सेल की महेतत की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आज के समय में मोबाइल केवल संचार का माध्यम नहीं रह गया।

सरपंच पति पर हितग्राहियों से रिश्तव मांगने का आरोप

जांजगीर-चांपा। पीएम आवास योजना में अवैध उगाही की शिकायत का मामला सामने आया है। कलेक्टर के पास कुछ ग्रामीणों ने पचरी गांव के सरपंच के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा है। उनका कहना है नवागढ़ ब्लॉक के पचरी गांव के सरपंच और उसके पति काम कराने के लिए 5 से 25 हजार रुपए तक की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक उनके पास फोन रिकॉर्डिंग भी है। जिसमें सरपंच पति कह रहा है कि पहला किस्त आपके अकाउंट में पहुंच गया है, उसमें से पांच हजार रुपये निकाल कर मुझे दो नहीं तो आगे का काम रुक जाएगा। इसके खिलाफ अब ग्रामीण और भीम रेजिमेंट के सदस्यों ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पचरी गांव की महिला सरपंच के पति का नाम नलसाय है। जो नवागढ़ स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक है, सरकारी नौकरी में होने के बाद भी सरपंच पति ही पंचायत का काम काज में पूरा दखल रखते हैं। शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ दिलाने के लिए हितग्राहियों से 5 से 25 हजार रुपये घुस मांगता है।

नारियल बुच जलाने की चिंगारी ने लिया विकराल रूप

सूरजपुर। जिले के प्रसिद्ध कुदरगढ़ देवी धाम मंदिर परिसर में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मची मंदिर परिसर में अगरबत्ती जलाने और नारियल फोड़ने वाले स्थान के पास आग की शुरुआत हुई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग मंदिर परिसर में रखी दान पेटी के समीप तक पहुंच गई और मनोकामना ज्योति कलश भवन में भी फैल गई, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। मंदिर परिसर में नारियल फोड़ने के बाद बचे हुए नारियल के बुच और अन्य सामग्री को जलाकर नष्ट किया जाता है। इसी दौरान निकली चिंगारी से आसपास रखे ज्वलनशील सामान में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही कुदरगढ़ चौकी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशकत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि मंदिर परिसर में हर रोज नारियल बुच को जलाकर नष्ट किया।

अंबिकापुर में पहली बार पिंक बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट

सरगुजा। सरगुजा में सराहनीय पहल की जा रही है। अंबिकापुर में हर साल महाराजा एमएस सिंहदेव क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होता है। इस वर्ष टूर्नामेंट को पिंक बॉल नाइट फॉर्मेट दिया है। ऐसा पहली बार होगा की यहां पिंक बॉल से क्रिकेट का एक नया फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। अंबिकापुर में सरगुजा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट अंडर-16 है। यानी 16 साल तक के बच्चे गांधी स्टेडियम में अपनी प्रतियोगिता को निखारते दिखेंगे। टूर्नामेंट 20-20 फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 12 युवा टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्य अतिथि हरिशंकर त्रिपाठी ने महाराजा एम एस सिंह देव के चित्र पर मालार्पण और दीप जलाकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। शरण सिंह देव ने टूर्नामेंट के लिए सरगुजा क्रिकेट संघ की टीम और सहयोगी संगठनों की सराहना की और उन्हें बधाई दी। आदिशेखर ने कहा कि इस तरह का आयोजन युवा खिलाड़ियों को फ्लड लाइट और उच्च दबाव वाले मैचों का अनुभव देगा।

सुशासन तिहार में सीएम का ऐलान, जनता का हित सर्वोपरि

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। 1 मई से छत्तीसगढ़ में जारी सुशासन तिहार तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। सुशासन तिहार में सीएम ने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम साय ने कहा कि सुशासन तिहार का मकसद जनता को तुरंत राहत प्रदान करना है। सीएम के साथ इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक भैयालाल राजवाड़े और चिरमिरी के महापौर रामनरेश मौजूद रहे। चिरमिरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम साय ने कहा कि सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता, संवेदनशील प्रशासन और त्वरित कार्रवाई की नीति पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने डायल 112 सेवा का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि यह सेवा आम जनता के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को तत्काल



सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार संसाधनों को मजबूत कर रही है। पुलिस और प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। चिरमिरी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना भी की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक भैयालाल रजवाड़े भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम साय ने भगवान जगन्नाथ से प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

राजा दिग्विजय दास स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह पर विवाद

■ **राजनांदगांव के ऐतिहासिक दिग्विजय दास स्टेडियम में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर समाज ने जताया विरोध**

राजनांदगांव। शहर के ऐतिहासिक महंत राजा दिग्विजय दास स्टेडियम में आयोजित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वैष्णव समाज के लोगों ने समारोह के आमंत्रण कार्ड में महंत राजा दिग्विजय दास की तस्वीर और नाम शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे राजा साहब का अपमान बताया। विरोध जताने बड़ी संख्या में समाज के लोग स्टेडियम पहुंच गए और कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाज के पदाधिकारियों का



कहना था कि जिस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति समाज और शहर के विकास के लिए दान दी, आज उसी के नाम और योगदान को आयोजकों ने नजरअंदाज किया है। वैष्णव समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि यह केवल एक प्रोटोकॉल की गलती नहीं, बल्कि समाज की भावनाओं को आहत करने वाला मामला है। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि वैष्णव

समाज की संपत्तियों और संस्थानों पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन मूल दानदाता और समाज की भूमिका को लगातार कमजोर किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यह भी कहा कि पूर्व में राजगामी संपदा न्यास में अध्यक्ष पद पर वैष्णव समाज के प्रतिनिधि की नियुक्ति की मांग उठाई गई थी, लेकिन उस मांग को भी अनसुना कर दिया गया। अब स्टेडियम के

कार्यक्रम में राजा साहब के नाम की उपेक्षा ने समाज में और नाराजगी पैदा कर दी है। विरोध के दौरान समाज के लोगों ने स्टेडियम परिसर में पहुंचकर भारेबाजी की और आयोजकों से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि भविष्य में भी समाज की भावनाओं की उपेक्षा की गई तो आंदोलन की अनपेक्ष किया जाएगा। हालांकि कार्यक्रम से जुड़े पदाधिकारियों की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आयोजन समिति के कुछ सदस्यों ने अनौपचारिक रूप से इसे डिजाईनिंग या प्रिंटिंग की त्रुटि बताया, लेकिन समाज के लोग इस तर्क से संतुष्ट नजर नहीं आए। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी पहुंचे थे।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ चाय व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष ने की राज्यपाल से सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से लोकभवन में छत्तीसगढ़ चाय व्यापारी संघ एवं छत्तीसगढ़ चौम्बर ऑफ कॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज़ के उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार बागड़ोदिया ने सौजन्य भेंट की। बागड़ोदिया ने बताया कि वे वर्ष 1964 से कोलकाता की टी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में वे रायपुर में चाय व्यवसाय के क्षेत्र में सक्रिय हैं।मुलाकात के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में चाय की खेती के संभावनाओं की जानकारी दी। राज्यपाल ने असम के चाय बागानों की तर्ज पर प्रदेश में भी चाय उद्योग के विकास के लिए विस्तार से चर्चा की और आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

कलेक्टर सिंह देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026 में शामिल

रायपुर। जिले के लिए गौरव का अवसर, फेम इंडिया और एशिया पोस्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026 विशेषांक में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को देशभर के टॉप कलेक्टर्स में हुए शामिल। उन्हें यह सम्मान उत्कृष्ट प्रशासन, नवाचार और प्रबंधन कौशल के लिए दिया गया है। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए मूल्यांकन में 10 प्रमुख मानकों के आधार पर देशभर के लगभग 800 जिलों के अधिकारियों का आकलन किया गया। इसमें से 100 सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों का चयन किया गया, जिनमें रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह भी शामिल हैं। विशेषांक में कलेक्टर डॉ. सिंह द्वारा जिले में जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक पारदर्शिता, नागरिक सेवाओं के सरलीकरण तथा नवाचारी पहलों को विशेष रूप से सराहा गया है।

रायपुर रेल मंडल में आज आयोजित होगा 49वां रोजगार मेला

रायपुर। शनिवार 23 मई को पूरे देश के 47 स्थान पर रोजगार मेला के तहत देशभर के 51 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी हेतु नियुक्ति पत्रों का वितरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। रोजगार मेला का आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, एन आई टी के सामने साइंस कॉलेज के पास रायपुर में 23 मई को आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में रेलवे, पोस्टल, वित्त सेवा ,स्वास्थ्य सेवा, हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड आदि विभागों में चयनित लगभग 257 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इससे न केवल चयनित अभ्यर्थियों को उनके भविष्य के निर्माण में एक सशक्त आधार मिलेगा, बल्कि यह पहल समूचे क्षेत्र के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बनेगी। रोजगार मेला के मुख्य अतिथि श्री दुर्गादास उइके जी माननीय जनजातीय केंद्रीय राज्य मंत्री रहेंगे। इस कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीया सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी रायपूर राज्य सभा सहित रायपुर शहर के माननीय विधायक श्री राजेश मृणत, पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू एवं रेलवे से मंडल रेल प्रबंधक श्री दयानंद एवं रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

खाद गबन मामले में बड़ी कार्रवाई प्रभारी शाखा प्रबंधक निलंबित

रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के दौरान आमजन की शिकायतों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कोरिया जिले की जिल्दा समिति, खड्गवा में खाद वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी कोरिया श्री कल्लु प्रसाद मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खाद वितरण में अनियमितता और गबन की शिकायतें सामने आने के बाद मामले की समीक्षा की गई। जांच में कार्रवाही के प्रति गंभीर लापरवाही उजागर होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आज श्री कल्लु प्रसाद मिश्रा, सहायक लेखापाल (प्रभारी शाखा प्रबंधक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शाखा बैंकुंपुर, जिला कोरिया निर्धारित किया गया है।

बकेला और नीर मध्यम जलाशय परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए 3.95 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कबीरधाम जिले की दो जलाशय योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य के लिए 03 करोड़ 95 लाख 08 हजार रुपये की राशि स्वीकृत किये हैं। विकासखण्ड-पण्डरिया की हाफ नदी में बकेला मध्यम जलाशय परियोजना के सर्वेक्षण के लिए 01 करोड़ 54 लाख 51 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार विकासखण्ड-बोड्डा की नीर नदी में नीर मध्यम जलाशय परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के लिए 02 करोड़ 40 लाख 57 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जलाशय परियोजनाओं के सर्वेक्षण कार्य कराने मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

नीति आयोग की रिपोर्ट: छत्तीसगढ़ के उसूर ब्लॉक को मिला दूसरा स्थान

मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई, कहा- यह सुशासन का प्रमाण, जनता के भरोसे की जीत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ‘सुशासन’ और जन कल्याणकारी नीतियों का असर अब राज्य के सबसे दूरस्थ अंचलों में दिखने लगा है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले से एक गौरवशाली खबर सामने आई है। नीति आयोग द्वारा जारी देश के आकांक्षी ब्लॉकों की ‘चैंपियंस ऑफ द क्वाटर्’ (अक्टूबर- दिसंबर 2025) की रिपोर्ट में बीजापुर के उसूर ब्लॉक ने सेंट्रल जोन में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर उसूर ब्लॉक और बीजापुर जिले के नागरिकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा, उसूर ब्लॉक का राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करना हमारे सुशासन और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष

प्रमाण है। बस्तर के सुदूर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उसूर ने कठिन परिस्थितियों में जो कर दिखाया है, वह पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा है। यह सफलता जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानिन बहनों, एएनएम और डॉक्टरों के समर्पण का परिणाम है। हमारा लक्ष्य अब देश में प्रथम स्थान हासिल करना है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में उसूर ब्लॉक की यह राष्ट्रीय सफलता बेहद गौरवशाली है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि हमारी सरकार की नीतियां प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पूरी प्रामाणिकता के साथ पहुंच रही हैं। कठिन



भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों और जिला प्रशासन ने जो समर्पण दिखाया है, वह सराहनीय है। हमारा संकल्प बस्तर के हर गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाना है।

मंत्री कश्यप ने कहा कि कभी बुनियादी सुविधाओं से दूर माना जाने वाला उसूर ब्लॉक आज देश के लिए विकास का मॉडल

बन गया है। इस सफलता का श्रेय जमीनी डॉक्टरों, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिन बहनों की दिन-रात की मेहनत को जाता है।

विकास की नई इबारत- कड़े मानकों पर खरा उतरा उसूर

नीति आयोग ने स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया था, जिसमें उसूर ब्लॉक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

संचारी रोगों पर नियंत्रण: मलेरिया, डेंगी और अन्य संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सुदूर गांवों तक प्रभावी अभियान चलाया गया।

सुरक्षित मातृत्व: संस्थागत प्रसव की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जिससे शिशु और मातृ मृत्यु दर में भारी कमी आई।

सशक्त टीकाकरण कवच: बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण के साथ एचपीवी टीकाकरण को जमीनी स्तर पर सफल बनाया गया।

गंभीर बीमारियों की जांच: बीपी, शुगर और कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों की मुफ्त जांच व उपचार की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचाई गई।

कलेक्टर विश्वदीप और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय गौरव पूरे जिले के लिए बड़ी प्रेरणा है। शासन और प्रशासन का अगला लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और निखारते हुए आगामी तिमाहियों में देश में पहला स्थान हासिल करना है, जिसके लिए काम तेज कर दिया गया है।

दीपक बैज के प्रधानमंत्री पर विवादित बयान से चढ़ा सियासी पारा

विदेश यात्रा से क्या उपलब्धि लेकर आए मोदी : अमरजीत भगत घटिया मानसकिता, ऐसे ही बयान से सिकुड़ रही है कांग्रेस : साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर दिए गए बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता पूरी तरह से बंटे हुए हैं। बयान पर गरमाई सियासत के बीच एक तरफ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत बयान का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव बयान को कांग्रेसियों की घटिया मानसिकता करार दे रहे हैं।

दीपक बैज के विवादित बयान पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि गलत क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में गए तो क्या उपलब्धि लेकर आए। सिर्फ टॉफी खिलाने और फोटो खिंचाने गए हैं क्या ?

इस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बहुत दुर्भाग्य है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी घटिया स्तर की राजनीति कर रही है। ये घटिया मानसिकता के लोग हैं। राहुल गांधी और पीसीसी चीफ बैज जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़क का आदमी भी उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। शब्दों की मर्यादा को तार-तार किया गया है। देश के लिए दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ऐसे बयान दे रही है। इन्होंने बयानों के कारण कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है।

सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री साय के कड़े



तेवर पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार चलाने के लिए जो तेवर अभी दिखा रहे, शुरुआत में ऐसा करते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आज भूमाफियाओं का प्रभाव बढ़ा है, सरगुजा से लेकर बस्तर तक भूमाफियाओं का जाल बिछा है। लोग जाएं तो कहां जाएं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं।

वहीं सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री की सख्ती पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के प्रति जवाबदेही का निर्वहन नहीं करेंगे, काम में लापरवाही करेंगे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनता सर्वोपरि है। जनता की मदद में कोई कोताही बरतेगा तो कार्रवाई होगी ही। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना जरूरी है।

वहीं खाद की किस्मत पर भगत ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन लोक कल्याण और किसानों के लिए काम नहीं कर

पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान को सांसद संतोष पांडेय ने बताया निंदनीय

रायपुर। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज है। देशभर में इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। राजनांदगांव से भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उनकी टिप्पणी को अभद्र और निंदनीय बताया है।

सांसद पांडेय ने कहा कि बस्तर में नक्सल समर्थक और सलवा जुद्धम के विरोध में निर्णय देने वाले बी सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाती है। इंडिया गेट पर नक्सली लीडर हिड्डमा के समर्थन में प्रदर्शनकी तस्वीरों को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था, क्या वह सेना के मनोबल गिराने का काम नहीं कर रहे? नक्सलियों का समर्थन नहीं कर रहे?

संतोष पांडेय ने कहा कि सेना की एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना वाले राहुल गांधी, किस मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन देश सेवा को समर्पित किया है, ऐसे नेता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पूरी तरह अनुचित है।



जल जीवन मिशन में लापरवाही 8 ग्रामों की निविदाएं निरस्त

रायपुर। जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसियों पर जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार 8 ग्रामों की निविदाएं निरस्त कर दी गईं।

कलेक्टर डॉ. सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समिति की बैठक में कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि रायपुर जिले के 8 ग्रामों में जल जीवन मिशन के कार्यों में कार्यरत निर्माण एजेंसियों द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए कार्य बंद कर दिया गया है। बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी इन एजेंसियों द्वारा कार्य पूर्ण करने में रुचि नहीं ली जा रही थी। पेयजल जैसी अतिआवश्यक सेवा के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कार्यपालन अभियंता को संबंधित निर्माण एजेंसियों के अनुबंध



तत्काल निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए।

इन ग्रामों की निविदाएं हुई निरस्त- आरंग ब्लॉक के ग्राम गोढ़ी, राटाकाट एवं मालीडीह, अभनपुर ब्लॉक के ग्राम हसदा एवं टीला, धरसीवा ब्लॉक के ग्राम सारागांव एवं तर्रा, तिल्दा ब्लॉक के ग्राम छपोरा शामिल हैं। साथ ही जल जीवन मिशन अंतर्गत आगामी निविदाओं में इन निर्माण एजेंसियों को वर्तित रखने तथा निरस्त निविदाओं में जमा राशि राजसात कर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। अब ये सभी निर्माण एजेंसियां भविष्य में जिले को जल जीवन मिशन की निविदाओं में भाग नहीं ले सकेंगी। जिले में लापरवाह एजेंसियों पर इस स्तर की बड़ी कार्यवाही पहली बार की गई है।

मुख्यमंत्री साय ने हितग्राहियों को अपने

हाथों से पहनाया नजर का चश्मा

सुशासन तिहार शिविर में स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल का किया निरीक्षण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुक्रवार को बलौदाबाजार जिले के करहीबाजार में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं और सेवाओं की जानकारी ली।

स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में मुख्यमंत्री ने 76 वर्षीय श्री गोवर्धन ध्रुव, 65 वर्षीय श्रीमती अनुपकुंवर पाल तथा कक्षा छठवीं के छात्र संजय चक्रधारी एवं जयसेन को अपने हाथों से



नजर का चश्मा पहनाया। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अब पढ़ने-लिखने और दैनिक कार्यों में काफी सुविधा

होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर उपचार और आवश्यक सहायता मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुशासन की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

//अधिसूचना//				
गरियाबंद दिनांक 08/05/2026				
भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013				
की धारा 4 सह परतिनियम 7 के अंतर्गत				
नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोकप्रयोजना हेतु राज्य सरकार द्वारा आयोजित है अर्थात :-				
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे)	लेक प्रयोजन का विवरण
गरियाबंद	अमलीपदर	गोलामाल	15.95 हे०	भेजीपदर व्यवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु
उपरोक्त उल्लेखित भूमि, के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जसमुनवाई (दिनांक) 25/05/2026 को (समय) 11.00 बजे से.... (स्थान) गोलामाल। पर नितीत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-				
(01) लोक प्रयोजन का संश्लिष विवरण-भेजीपदर व्यवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य। (02) प्रत्यक्ष रूप से प्राप्तावित परिवारों की संख्या 63. (03)अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्तावित परिवारों की संख्या - निरंक (04) प्राप्तावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसरमयितियों की अनुमाति संख्या-निरंक। (05) प्राप्तावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसरमयितियों की अनुमाति संख्या-निरंक। (06) प्राप्तावित अर्जन न्युतम है-हॉ (07) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है-हॉ (08) परियोजना को लागत-2977.74 लाख। (09) परियोजना से होने वाला लाभ-कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। (10) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला अर्थ-व्यय-निरंक। (11) परियोजना द्वारा प्राप्तावित होने वाले अन्य अर्थ-व्यय-निरंक।				
उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो, तो विरहित तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।				
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार				
कलेक्टर गरियाबंद एवं पदेन उप सचिव छग० शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग				
भू-अर्जन अधिकारी मैनपुर				
जी-262700898/3				

पीएम मोदी की विदेश यात्रा का महत्व

आनंद कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों-संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा केवल एक सामान्य कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि भारत के सामने खड़ी एक गंभीर आर्थिक व भू-राजनीतिक चुनौती का रणनीतिक उत्तर थी। पश्चिम एशियाई संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत के सामने चिंताएं पैदा कर दी हैं। ऐसे में, प्रधानमंत्री को यह यात्रा भारत को ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने, प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने और यूरोप तथा पश्चिम एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने का प्रयास थी। यह यात्रा संकेत थी कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत अपनी विदेश नीति को पुनर्गठित कर रहा है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यूएई था। इस दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर सहमति व्यक्त की। यूएई के हाल ही में ओपेक से बाहर निकलने से उसे तेल उत्पादन बढ़ाने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, जिसका लाभ भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को मिल सकता है। यूएई-भारत के बीच किए गए ऊर्जा समझौते दर्शाते हैं कि भारत ऊर्जा संकट से बचने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था बना रहा है। भारत के ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्रों में बढ़ता यूएई निवेश भारत की अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय विश्वास को भी दर्शाता है। यूरोप यात्रा के चरण में नीदरलैंड के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। सेमीकंडक्टर तकनीक, समुद्री अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में डच विशेषज्ञता भारत की विकास आवश्यकताओं के अनुकूल है। नीदरलैंड द्वारा चोलकालीन ऐतिहासिक ताम्रपत्रों की वापसी ने दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को भी नई मजबूती दी। स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा ने यह दिखाया कि भारत अब नॉर्डिक देशों को भविष्य की प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था के प्रमुख साझेदार के रूप में देख रहा है। 'इंडिया-स्वीडन जॉइंट इन्वेस्टमेंशन पार्टनरशिप 2.0' और एआई कॉरिडोर जैसी पहलें भविष्य उन्मुख साझेदारी का उदाहरण हैं। भारत ने स्वीडन के साथ व्यापार और निवेश को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है। भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नियम-आधारित व्यवस्था, लोकतंत्र और बहुपक्षवाद पर जोर ने वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत और यूरोपीय लोकतंत्रों की बढ़ती रणनीतिक निकटता को दर्शाया। भारत-इटली संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाना दर्शाता है कि भारत दक्षिणी यूरोप व भूमध्यसागरीय क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को नई दिशा देने का चाहता है। 'डेवलप इन इंडिया एंड इटली, डिलीवर टू द वर्ल्ड' जैसी अवधारणा भारत की वैश्विक आपूर्ति शृंखला में केंद्रीय भूमिका निभाने की ही कोशिश है। यह यात्रा भारत की विदेश नीति के बदलते स्वरूप को दर्शाती है। भारत एक ऐसे समय में अपनी वैश्विक भूमिका को पुनर्परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, जब दुनिया ऊर्जा संकट, भू-राजनीतिक तनाव और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रही है। हालांकि, इन समझौतों और घोषणाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें कितने प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। फिर भी यह स्पष्ट है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि यूरोप, पश्चिम एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सेतु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे....)

मनु की नाक से इक्ष्वाकु

विष्णु-पुराण में लिखा है कि मनु राजा के छींकते हुवे ग्राण से प्रसिद्ध इक्ष्वाकु पुत्र पैदा हुवा। यथा-
श्रुवतश्च मनोरिक्ष्वाकुर्याणतः पुत्रो जज्ञे।

(विष्णुपुराण अंश 4 ओ 2 श्लो0 16-183)

यहु बात चण्डूखाने की गप्प के बराबर है।

समाधान

वेदादि शास्त्रों का यह सर्वतन्त्र सिद्धांत है कि सृष्टि दो प्रकार की होती है- (1) मैथुनी और (2) अमैथुनी, अर्थात् माता पिता के संभोग से उत्पन्न होने वाली और अनिवर्चनीय प्रकृति के नियन्त्रण से अपने आप इच्छा मात्र से उत्पन्न होने वाली। वैदिक साहित्य में उक्त दोनों तरह की सृष्टियों का खुला वर्णन आता है। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हम रात दिन देखते हैं, अतः हमें इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होता। परन्तु अमैथुनी सृष्टि के मनुष्य अतीतकाल के गर्भ में

विलीन हो चुके हैं, अतः अब उनकी उत्पत्ति हमें कुतूहल-जनक जान पड़ती है।

यदि अन्तर्मुखी होकर विचार किया जाये तो मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव भी कम आश्चर्य का विषय नहीं, क्योंकि माता के उदर की जाटराग्नि में माता के भक्षण किये हुवे कैङ्दे से कैङ्दे पदार्थ भी यहां तक कि मांसाहारी जातिकी स्त्रियों की जाटराग्नि में तो माँस-अस्थि-खण्ड तक उसी जाटराग्नि के घककते किया हुआ अकिञ्चित्कर दशवें महीने में सर्वाङ्ग-सुन्दर क्या यह कुछ कम अचम्भे की भी कुछ घण्टे में ही भस्मसात् हो जाते हैं, हुवे कुण्ड के एक कोने में पिता का सेचन वीर्य्यकण तथैव सुरक्षित रहता हुआ बालक के रूप में प्रादुर्भूत होता है, बात है ?

परन्तु निरन्तर देखने के कारण हमें इसमें कुछ भी कौतुक नहीं दीख पड़ता। यह तो हुई मैथुनी सृष्टि की बात।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

राजनीति सनातन विरोध की बजाय आममुद्दों पर हो

ललित गर्ग

भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में एक ऐसा विमर्श लगातार उभर रहा है, जिसने राजनीतिक बहस को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मूल प्रश्नों से हटाकर धार्मिक पहचान और आस्था के इर्द-गिर्द खड़ा कर दिया है। यह विमर्श है-सनातन समर्थन बनाम सनातन विरोध। आज देश में एक ओर सनातन संस्कृति को भारतीय जीवन का शाश्वत आधार मानने वाली शक्तियां हैं, तो दूसरी ओर कुछ राजनीतिक वक्तव्य और प्रवृत्तियां ऐसी दिखती हैं जिन्हें जनमानस सनातन विरोध के रूप में देखता है। प्रश्न यह नहीं कि किसी विचारधारा से सहमति या असहमति क्यों है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या राजनीति का केंद्र धर्म होना चाहिए या जनजीवन के वास्तविक मुद्दे? भारत का लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष संविधान पर आधारित है, जहां राज्य का कार्य किसी धर्म का पक्ष या विरोध नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। राजनीतिक दलों का दायित्व भी यही होना चाहिए कि वे जनता की समस्याओं, विकास और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक विमर्श राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है।

सनातन केवल एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक चेतना, जीवन-दर्शन और मूल्य परंपरा का प्रतीक है। सत्यं वद, धर्मं चर, वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे सूत्र इसी सनातन दृष्टि के अंग हैं। इसलिए जब कोई राजनीतिक वक्तव्य सनातन को लेकर अपमानजनक या आक्रामक भाषा का उपयोग करता है, तो उसका प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पर भी पड़ता है। तमिलनाडु में द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करने वाला वक्तव्य इसी कारण व्यापक विवाद का कारण बना। विपक्ष के अनेक दलों ने उससे दूरी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत जैसे देश में करोड़ों लोगों की आस्था को आहत करने वाला कथन राजनीतिक रूप से भी असहज स्थिति उत्पन्न करेगा। यहां यह समझना आवश्यक है कि द्रविड़ आंदोलन की अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक प्रभुभूमि रही है। उसका मूल संघर्ष सामाजिक विभ्रमताओं और जातीय वर्चस्व के विरुद्ध था। लेकिन जब सामाजिक सुधार का



विमर्श पूरे धर्म या संस्कृति के विरोध जैसा प्रतीत होने लगे, तब वह जनस्वीकृत खो देता है।

यह भी सत्य है कि अनेक विपक्षी दल स्वयं को सनातन विरोधी नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद और भेदभाव के विरोधी बताते हैं। उनका तर्क है कि वे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। यह दृष्टि लोकतंत्र में स्वीकार्य है, क्योंकि हर परंपरा में आत्मसमीक्षा और सुधार की आवश्यकता होती है। स्वयं भारतीय दर्शन में भी संवाद, बहस और आत्मचिंतन की परंपरा रही है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दयानंद और गांधी-सभी ने समाज की विसंतियों पर प्रश्न उठाए, लेकिन उन्होंने समाज को तोड़ने नहीं, सुधारने का मार्ग चुना। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक भाषा संतुलन खो देती है। जब आलोचना सुधार की जगह अस्वीकार की भाषा बन जाती है, तब वह समाज में ध्ववीकरण को जन्म देती है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं कही जा सकती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का विमर्श अधिक प्रभावी होकर उभरा है। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान जैसे विषयों ने एक बड़े वर्ग में सांस्कृतिक आत्मविश्वास को मजबूत किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ भी मिला। दूसरी ओर विपक्षी दल इस बदलते राजनीतिक मानस को समझने में कई बार असहज दिखाई दिए। कहीं उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और आस्था के बीच संतुलन बनाने में चूक की, तो कहीं उनके कुछ नेताओं के बयान उन्हें कठिन स्थिति में ले आए। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक चुनावी रणनीति में यह देखा गया कि केवल जातीय समीकरण या पारंपरिक वोट बैंक अब पर्याप्त नहीं हैं। जनता सांस्कृतिक पहचान, विकास और राष्ट्रीय विमर्श को भी महत्व देने लगी है। ऐसे में यदि कोई दल

हिंदू आस्था के प्रति असंवेदनशील दिखता है, तो उसका राजनीतिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे विमर्श का दूसरा पक्ष भी है। क्या राजनीति का उद्देश्य केवल धार्मिक पहचान के आधार पर समर्थन जुटाना होना चाहिए? क्या देश के सामने मौजूद बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि संकट, आर्थिक असमानता और सामाजिक विघटन जैसे प्रश्न पीछे छूट जाने चाहिए? यह चिंता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के दौरान धर्म, विशेषकर सनातन और हिंदू आस्था को लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक आदि विपक्षी दलों एवं उनके कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को व्यापक जनसमुदाय ने सनातन पर आक्षेप या हिंदू भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता के रूप में देखा, जिसके राजनीतिक प्रभाव भी दिखाई दिए। किंतु इस विषय को केवल हिंदू विरोध बनाम राजनीतिक विरोध के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। भारत एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी राष्ट्र है, जहां किसी भी राजनीतिक दल को सरकार, नीतियों या नेतृत्व का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यदि वह विरोध आस्था, संस्कृति और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से टकराता हुआ प्रतीत हो, तो उसका राजनीतिक मूल्य चुकाना पड़ सकता है। यही कारण है कि कई दलों के लिए यह धारणा चुनौती बनी कि वे सत्ता-विरोध की राजनीति करते-करते सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं से दूर हो गए हैं। भारत में सनातन केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन, परंपरा, संस्कृति, सहिष्णुता और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसके प्रति असावधान भाषा या नकारात्मक संकेत जनमानस में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करते रहे हैं। दूसरी ओर लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा यह भी अपेक्षा करती है कि राजनीतिक विमर्श व्यक्तियों, नीतियों और शासन के मुद्दों पर केंद्रित रहे, न कि धार्मिक ध्रुवीकरण पर।

राजनीतिक दलों के लिए यह आवश्यक है कि वे मतभेद रखें, आलोचना करें, लेकिन भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक संवेदनशीलता और आस्था के सम्मान का संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जनता अंततः उसी नेतृत्व को स्वीकार करती है जो उसकी भावनाओं, परंपराओं और राष्ट्रीय मानस को समझने का प्रयास करता है। भारत की राजनीति

विश्व कछुआ दिवस



बहुत दीर्घायु होता है इसलिए यह भी मान्यता है कि कछुए की मूर्ति घर में रखने से परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होगी वास्तु शास्त्र में तो कछुए को सुख समृद्धि शांति का प्रतीक माना जाता है।

कछुआ दिवस मनाने के पीछे कारण यह है कि कछुए धरती पर बहुत पुराने जीव हैं और इनका संरक्षण प्राकृतिक संतुलन और जैविक विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये समुद्री और स्थलीय परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समुद्र और धरती दोनों में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाते हैं। समुद्री कछुए समुद्री पौधों और शैवाल को नियंत्रित करते हैं और स्थलीय कछुए मिट्टी को उर्वरता में मदद करते हैं। इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है।

विश्व कछुआ दिवस का आयोजन American Tortoise Rescue (ATR) द्वारा किया जाता है, यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो कछुओं के संरक्षण के लिए काम करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कछुओं की जागरूकता बढ़ाना, उनकी संरक्षण के लिए कानूनी कदम उठाना, उनके लिए स्थाई निवास स्थलों की रक्षा करना, और उनकी देखभाल करना।ATR कछुओं के हितों की रक्षा के लिए काम करता है।

कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक है । ये लगभग 200 मिलियन वर्ष पुरानी प्रजाति

है और चिड़ियों ,सांपों और छिपकलियों से भी पहले धरती पर अस्तित्व में आ चुकी थी। पारितंत्र में कछुओं का अस्तित्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक स्वस्थ पर्यावरण के संकेतक माने जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में इनका अहम स्थान है और पौधों व मछलियों की कई ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके नियंत्रण के लिए कछुओं को अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

आज विश्व में कछुओं की 300 से भी अधिक प्रजातियाँ हैं जिनमें से लगभग 130 IUCN के द्वारा संकटापन्न घोषित की गई हैं । भारत में कछुओं की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें 24 प्रजाति कच्छप अर्थात स्थलीय कछुए के एवं 5 प्रजाति कुर्म अर्थात समुद्री कछुओं के हैं। इनमें से अधिकांश कछुए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न अनुसूचियों के अन्तर्गत संरक्षित हैं।

आज का इतिहास

- 1430 सौ साल के युद्ध जोन ऑफ आर्क को कॉम्मेजेन की घेराबंदी पर कब्जा कर लिया गया था।
- 1498 फ्लोरेंस के जियोल्मो सवोनारोलो को विधर्मियों, भविष्यवाणियों और अन्य अपराधों के लिए किया गया था।
- 1533 केंटरबरी के आर्कबिशप थॉमस क्रैमर ने अपनी पहली पत्नी, वैराग्य की कैथरीन, आठवीं की शादी को रद्द कर दिया, जो कि अंग्रेजी सुधार में होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला है।
- 1701 स्कॉटिश निजी व्यक्ति विलियम किड को चोरी के लिए मार दिया गया था।
- 1706 जॉन चर्चिल (मार्लबोरो का राजकुमार) ने फ्रांस को हराया, जिसमे 17,000 लोग मारे गए।
- 1707 सेंटोरीनो काल्डेरा में ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हुआ।
- 1844 सय्यद -अली-मुहम्मद शिराज़ी ने घोषणा की कि वह शिया धर्म की अवधारणा के बाद b बब 'था, बबी आंदोलन की शुरुआत के साथ, बहाई आस्था का अग्रदूत।
- 1848 लिलिएनथाल का जन्म। इन्होंने ईसान को पहली बार उड़ना सिखाया। उनकी उड़ान ने क्रांति कर दी।
- 1873 नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के अग्रदूत, कानून और व्यवस्था लाने और नॉर्थवेस्ट टेरिटरी पर कानडाई संप्रभुता का दावा करने के लिए स्थापित किया गया था।
- 1879 रूसी लेखक इवान तुर्गेनेफ़ को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने नागरिक कानून में डॉक्टरेट की उपाधि दी। वे दुनिया के ऐसे पहले लेखक थे, जिसे यह सम्मान दिया गया था।
- 1895 एक्टर लाइब्रेरी और लेनॉक्स लाइब्रेरी के प्रतिनिधियों ने विलय कर दिया और न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी का गठन किया, जो अब संयुक्त राज्य में दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी लाइब्रेरी है।
- 1904 वियेना में पहली कुश्ती विश्व चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था।
- 1915 किंगटिशल रेल दुर्घटना 22 मई, 1915 को स्कॉटलैंड के ग्रेटा ग्रीन, ड्युमिसशायर के पास हुई, जिसमें 5 गाड़ियां शामिल थीं। यह मृत्यु के मामले में यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में सबसे खराब रेल दुर्घटना थी, इस दुर्घटना में 226 लोग मारे गए थे और 246 घायल हुए थे।
- 1915 प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली ने आस्ट्रिया, हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।
- 1934 अमेरिकी अपराधियों बोनी पार्कर और क्लाइड बैरो लुइसियाना के बिगएनविलेपिरिश में अपने ठिकाने के पास एक उजाड़ सड़क पर पुलिस द्वारा घात लगाकर मारे गए।

मोदी के आह्वान का विरोध व आलोचनाएं केवल राजनीतिक

अवधेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पैट्रोलियम पदार्थों के हर संभव न्यूनतम उपयोग के साथ अन्य अपोलों व कदमों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में आलोचना व विरोध के स्वर ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री ने 10 मई को देशवासियों से मुख्यत् 3 अपोलैं कीं, जिनमें एक साल तक सोने की खरीद टालने, गैर जरूरी विदेश यात्राएं न करने और पैट्रोल–डीजल की बचत के लिए वर्क फ्रॉम होम और कार पूक्षलव ग सार्वजनिक यातायात का ज्यादा इस्तेमाल करना शामिल है।

हालांकि विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कहा जा रहा है कि चुनाव तक प्रधानमंत्री को संकट नहीं दिखा और अचानक दिख गया। पैट्रोल–डीजल के दाम बढ़े हैं तो आरोप यह है कि बस केवल चुनाव तक रोका गया था। इस तरह की अनेक आलोचनाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने अपील के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में जाते समय अपने काफिले को कम किया तथा केवल 2 गाड़ियां दिखाई थीं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं अन्य मंत्रियों ने भी अपने काफिले से गाड़ियों की संख्या कम की। इसके

बाद पूरे देश से इस तरह की तस्वीरें और निर्णय आए, जहां भाजपा सरकारों के मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या में कटौती की, स्वयं तथा सरकारी अधिकारियों के कार्यालय जाने की व्यवस्था में बदलाव किया और कई जगह ससाह में निश्चित दिन वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की अनुमति दी गई। इस तरह के कदमों से कई बार आशंका पैदा होती है मानो देश गंभीर संकट में है और लोगों से मितव्ययिता यानी कम खर्च करने को कहा जा रहा हो। विरोध और प्रतिक्रियाएं भी संदेहों को बढ़ावा देतीं हैं।

वस्तुत् विरोध व आलोचनाओं में राजनीति ज्यादा है। कुछ गलतफहमियां भी पैदा की जा रही हैं। यह केवल विदेशी मुद्रा वाले खर्च में कमी करने संबंधी अपील है। फिर प्रधानमंत्री ने अपील की है, कोई नियम–कानून नहीं बना कि जिससे न मानने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो जाए। दूसरे, इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़े संकट में है। प्रधानमंत्री को अपील में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के लिए ‘वोकल फॉर लोकल’ की भी बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति संतोषजनक है। विदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग 697 अरब



डॉलर है, जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। महंगाई थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है लेकिन खाद्य वस्तुओं का महंगाई दर नियंत्रण में है। किंतु भारत एक बड़ा आयातक देश है। हम कच्चे तेल का करीब 89 प्रतिशत आयात करते हैं तो सोने का 90 प्रतिशत से ज्यादा। हमारे कुल आयात बिल में 4 मर्दों में सबसे ज्यादा खर्च हैं। कच्चे तेल पर 2025–26 में कुल 134.7 अरब डॉलर का खर्च आया तो सोने पर 72 अरब डॉलर, खाने के तेल पर 19.5 अरब डॉलर और उर्वरक पर 14.5 अरब डॉलर।

ईरान अमरीका इसराइल युद्ध ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल पैदा की है। होम्पुंज संकट ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका तीनों के लिए समस्या पैदा की है, जिसका समाधान नहीं हो रहा। युद्ध कब समाप्त होगा, क्या मोड़

लेगा, कहना कठिन है। कोई वैश्विक संस्था इतनी प्रभावी नहीं जो व्यापार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, समुद्री परिचालन आदि के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करा सके। पूरी दुनिया की आपूर्ति शृंखला बाधित ही नहीं है उथल-पुथल के दौर में है।

अभी तक आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की काफी हद तक भरपाई निर्यात तथा रेमिटेंस यानी विदेश में कार्यरत या रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा से हो जाती थी। इस कारण चालू खाते का घाटा हमेशा नियंत्रण में रहा। वर्ष 2024 में विदेशी में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए धन की मात्रा 138 अरब डालर थी। अप्रैल से सितम्बर 2025 तक यह पिछले वर्ष के 64.7 अरब डॉलर से बढ़कर 73 अरब डालर हो गया था। खाड़ी युद्ध और वैश्विक संकट के कारण इसमें व्यापक कमी की संभावना पैदा हो गई है। इसी तरह वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का कुल निर्यात (माल और सेवाएं) 4.22 प्रतिशत बढ़कर 860 अरब डॉलर से अधिक हो गया, जबकि आयात लगभग 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 979 अरब डॉलर तक पहुंचा। आपूर्ति शृंखला बाधित होने से हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है। किंतु मूल्य बढ़ते रहने के बावजूद

कमलेश पांडे

बिहार की राजनीति में जुझारू युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को केवल सुलझते हुए वर्तमान का एक नेता ही नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीतिक धुरी के रूप में देखने वालों की संख्या पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ती ही जा रही है और यह सिलसिला निरंतर आगे भी चलता रहेगा। ऐसा इसलिए कि उनके पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक कारण सक्रिय हैं, जो उन्हें राजनीतिक रूप से अजेय बनाते हैं। आइए इन्हें समझते हैं विस्तार से–

पहला, बिहार में भाजपा के भोष्म पितामह कैलाशपति मिश्रा के संजोए हुए सपनों को पूरा करते हुए पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बनने का ऐतिहासिक महत्व है। निःसन्देह साल 2026 में सम्राट चौधरी का बिहार का मुख्यमंत्री बनना भाजपा के लिए ऐतिहासिक मोड़ माना गया, क्योंकि पहली बार बिहार में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद अपने हाथ में लिया। इससे प्रदेशवासियों में यह संदेश गया कि भाजपा अब बिहार में जूटियर पार्टनर नहीं रहना चाहती बल्कि पार्टी ने बिहार में अपना सूझबूझ युक्त स्वतंत्र नेतृत्व स्थापित कर दिया।

पार्टी मामलों के जानकारों की मांनें तो अब सम्राट चौधरी को केवल अंतरिम चेहरा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नेतृत्व के मोहरे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो ओबीसी सियासत के लिए सौभाग्य की बात है। चूंकि उनमें सामाजिक न्याय के सूत्रधार लालू प्रसाद वाली हाजिर जवाबी, सुशासन बाबू नीतीश कुमार वाली सियासी चतुराई के अलावा सद्भावी कैलाशपति मिश्रा वाली सूझबूझ भी भरी हुई है जिससे हरेक जाति–धर्म के लोगों में उनकी स्वीकार्यता दिनप्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

दूसरा, सामाजिक समीकरणों में मजबूत पकड़: बिहार की राजनीति के भाजपाई नव चाणक्य सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा राजनीतिक बल उनका व्यापक सामाजिक आधार माना जाता है। चूंकि वे पिछड़े वर्ग, विशेषकर कुशवाहा–कोइरी यानी लव कुश समाज या त्रिवेणी संघ से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में निर्णायक प्रभाव रखता है। इससे भाजपा को लालू प्रसादनीतीश कुमार के सामाजिक न्याय के बीच यादव



जो हिंदुत्व, ओबीसी राजनीति, और संगठनात्मक निष्ठा तीनों को एक साथ लेकर चल सके। लिहाजा सम्राट चौधरी उस समीकरण में फिट बैठते दिखे। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, वैश्य, दलितों के साथ–साथ प्रगतिशील यादवों पर भी पूरी पकड़ है, जिसका फायदा भाजपा नीत एनएई को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उन्होंने दिलवाया और पुरस्कार स्वरूप पहले गृहमंत्री, फिर मुख्यमंत्री बने।

तीसरा, व्यवहारिक आक्रामक भरा लेकिन नियंत्रित राजनीतिक शैली: राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि सम्राट चौधरी की राजनीति, तेजस्वी यादव की तरह ही पलटवारी आक्रामक, लेकिन संगठन के प्रति अनुशासित मानी जाती है। वे सड़क से लेकर सदन तक मुखर सियासी शैली अपनाते रहे हैं। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा हुई। भाजपा नेतृत्व अक्सर ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाता है जो जनसभाओं में भीड़ खींच सकें, विपक्ष पर हमला कर सकें, और संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहें। ये सभी गुण सम्राट चौधरी में कूट कूट कर भरें हुए हैं। इसलिए उनका सियासी उदय पूर्वी भारत की राजनीति में अहम मायने रखती है।

चौथा, दिल्ली नेतृत्व का भरोसा: भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की राजनीति में विश्वसनीय नेतृत्व बहुत महत्व रखता है। चूंकि सम्राट चौधरी इन कसौटियों पर भी खरे उतरते हैं, इसलिए उनपर सबका भरोसा बढ़ा है। वाकई सम्राट चौधरी जमीनी संगठन से निकले नेता हैं, जो भाजपा की स्थापित लाइन से थोड़ा–सा भी विचलित नहीं होते, और गठबंधन राजनीति को भी संभालने की क्षमता

पैट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए शुल्क घटा चुकी है। खाद की 2200 रुपए की बोरी 242 रुपए में मिल रही है। लगभग 82 देशों में पैट्रोल–डीजल की राशनिंग हो रही है। दक्षिण–पूर्व एशिया में तेल 50 प्रतिशत और यूरोप में 20 प्रतिशत महंगा हो चुका है। भारत में इसे नियंत्रित रखा गया है। आम लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि जब वैश्विक संकट है तो दाम बढ़ेंगे ही और अनेक कह रहे हैं कि ज्यादा बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे यह कम है। इसका अर्थ हुआ आम लोग इसके लिए तैयार हैं।

विदेशी मुद्रा की भविष्य की चुनौतियों के बीच सुरक्षा की गारंटी है। 1991 में विदेशी मुद्रा संकट के कारण प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सरकार को 67 टन सोना विदेश में गिरवी रखकर 2000 करोड़ डॉलर का कर्ज लेना पड़ा था। उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार को भी 45 दिनों में करीब 47 टन सोना और गिरवी रखना पड़ा, ताकि भारत 4000 करोड़ डॉलर सरकार चलाना नहीं, बल्कि अगले 10ड्ड्रा15 वर्षों का राष्ट्रवादी राजनीतिक आधार तैयार करना भी माना जा रहा था। पार्टी की इस रणनीति को अमलीजामा पहनाने के प्रति सम्राट चौधरी ने भी प्रतिबद्धता दिखाई है।

छठ, सत्तापतिष्ठान की राह में चुनौतियाँ भी कम नहीं: हालाँकि सम्राट चौधरी के सामने कतिपय बड़ी चुनौतियाँ हैं, जिसमें बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य, जातीय संतुलन, और गठबंधन राजनीति के प्रबंधन में सम्राट चौधरी निरंतर सही चाल चल रहे हैं और अहम फैसले ले रहे हैं। इससे बिहार वासियों के दिलोदिमाग पर सकारात्मक असर पड़ा है। भले ही सियासी ईर्ष्यावश विपक्ष लगातार उनकी सरकार को अपराध और प्रशासनिक मुद्दों पर घेर रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी लगातार विकास, रोजगार, और प्रशासनिक सुधार पर ठोस परिणाम देते । नजर आते हैं, इसलिए सूबे में भविष्य के नेता वाली उनकी छवि स्थायी बनती जा रही है।

सातवां, बिहार की नई राजनीतिक कथा के अहम सूत्रधार और नेतृत्वकर्ता: सम्राट चौधरी का उदय केवल व्यक्ति विशेष का उत्थान नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में तीन बड़े परिवर्तनों का संकेत माना जा रहा है– पहला, भाजपा का स्वतंत्र प्रभुत्व, दूसरा, ओबीसी नेतृत्व का नया संस्करण, और तीसरा, पोस्ट–नीतीश युग की शुरुआत। चूंकि इस नई राजनीतिक कथा के अहम सूत्रधार और नेतृत्वकर्ता खुद सम्राट चौधरी ही हैं, इसीलिए समर्थक उन्हें बिहार का वर्तमान और भविष्य दोनों कह रहे हैं।

1975 का आक्रोश और 2026 का बेचैन भारत?

सनत जैन

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 1975 केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि सत्ता, आर्थिक संकट और जनक्रोश के टकराव का प्रतीकी भी है। 2026 में देश की परिस्थितियों को देखकर बार–बार 1975 की महंगाई का वही प्रश्न उठता है, क्या भारत फिर किसी बड़े राजनीतिक और सामाजिक विस्फोट की ओर बढ़ रहा है? जिसमें सत्ता का परिवर्तन भी हुआ था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर बांग्लादेश का निर्माण कराया था। करीब एक करोड़ शरणार्थियों का बोझ भारत ने उठाया। पाकिस्तानी सेना के 95000 से अधिक जवान आत्मसमर्पण कर भारत में रहे। युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध ने तेल संकट और आर्थिक प्रतिबंधों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। पेट्रोल, डीजल और खाद्यान्न की कमी ने महंगाई को विस्फोटक बना दिया। इंदिरा गांधी 1971 का युद्ध जीतकर दुर्गा कहलायीं, लेकिन 1974 आते–आते जनता की नजर में वही इंदिरा गांधी की सरकार महंगाई और बेरोजगारी की प्रतीक बन गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया गया, इसने आंदोलन की आग में घी डालने और आंदोलन को उग्र किया। छात्र, कर्मचारी, ट्रेड यूनियन और विपक्ष एक मंच पर आ गए। जयप्रकाश नारायण ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। रेलवे हड़ताल से लेकर विश्वविद्यालयों के छात्र आंदोलनों तक से देश उबाल पर था।

जेपी ने पुलिस और सेना को सरकार के आदेश नहीं मानने का आह्वान किया। जब सरकार को लगा कि आंदोलन नियंत्रित करना संभव नहीं है, सत्ता हाथ से निकल सकती है, तब 25 जून 1975 को सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया। लोकतंत्र को कुचलने की वह कीमत अंततः कांग्रेस को 1977 के चुनाव में चुकानी पड़ी। उत्तर भारत में कांग्रेस की करारी पराजय हुई।

आज का भारत भले तकनीकी रूप से आधुनिक हो। आर्थिक और सामाजिक बेचैनी 1975 जैसी खतरनाक स्तर तक बढ़ती हुई दिख रही है। रुपया लगातार गिर रहा है। 97 के स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, आयात बढ़ गया है। विदेशी मुद्रा का

अतिक्रमणकारियों के पास अचानक इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं?

नीरज कुमार दुबे

मुंबई के लिए मुसीबत बने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पुलिस और प्रशासन ने कराार सबक सिखाकर देश की आर्थिक राजधानी को बड़ी राहत दिलाई है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर इलाके में पश्चिम रेलवे द्वारा चलाया जा रहा अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान न केवल रेलवे भूमि को मुक्त कराने की दिशा में अहम कदम साबित हुआ, बल्कि इस कार्रवाई ने यह भी उजागर कर दिया कि किस तरह अवैध कब्जाधारी कानून व्यवस्था को चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटते। कार्रवाई के दौरान पुलिस और नए विधेय अधिकारियों पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिससे एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि देश के किसी भी हिस्से में अतिक्रमण हटाने या अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलते ही इन घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के पास अचानक इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं?

उल्लेखनीय है कि पश्चिम रेलवे ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के निकट गरीब नगर में फैले अवैध कब्जों को हटाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। यह मुंबई में रेलवे की अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई मानी जा रही है। रेलवे के अनुसार लगभग पांच हजार दो सौ वर्ग मीटर भूमि को खाली कराया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब छह सौ करोड़ रुपये आंकी गई है। यह इलाका हार्बर लाइन की पटरियों और बिजली व्यवस्था के बेहद करीब पहुंच चुका था, जिससे रेल संचालन और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यहां कई बहुमंजिला झुग्गियां फुटओवर पुलों की ऊंचाई से भी ऊपर तक बना दी गई थीं। इससे भविष्य की रेलवे परियोजनाओं और ट्रेनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। रेलवे लंबे समय से इस भूमि को खाली कराना चाहता था, क्योंकि बांद्रा स्टेशन और बांद्रा कुर्ला परिसर के पास स्थित यह इलाका रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस मामले में कानूनी प्रक्रिया वर्ष 2017 से



पहले शुरू हो चुकी थी। सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 27 नवंबर 2017 को बेदखली आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद मामला बंबई उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। इस वर्ष 29 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने अवैध अतिक्रमण हटाने की अनुमति दी थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी इस आदेश पर रोक नहीं लगाई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी।

पश्चिम रेलवे ने करीब पांच सौ झुग्गियों को हटाने के लिए चिन्हित किया, जबकि संयुक्त सर्वेक्षण में पात्र पाए गए लगभग एक सौ ढांचों को फिलहाल नहीं छुआ गया। रेलवे का कहना है कि भविष्य में इस जमीन का उपयोग उपनगरीय और लंबी दूरी की रेल सेवाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा। कार्रवाई को सफल बनाने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। करीब चार सौ पुलिसकर्मी, चार सौ रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस के जवान तथा लगभग दो सौ रेलवे अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए। बांद्रा स्टेशन और बांद्रा टर्मिनस के आसपास कई रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे भारी यातायात जाम लग गया और यात्रियों को सामान लेकर पैदल चलना पड़ा।

शुरुआत में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, लेकिन दूसरे दिन दोपहर बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। अधिकारियों ने जब एक अवैध मस्जिद और वहां लगाए गए निजी दूरसंचार टावर को हटाने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासनिक टीमों पर पत्थर, बर्तन और अन्य सामान फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।

इस हिंसा में सात पुलिसकर्मी और छह प्रदर्शनकारी घायल हुए। पुलिस ने दस लोगों को हिरासत में लिया और निर्मल नगर पुलिस थाने में गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। घायलों का उपचार भाभा अस्पताल और वीएन देसाई अस्पताल में कराया गया। एक पुलिसकर्मी और एक प्रदर्शनकारी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, हालांकि दोनों की हालत स्थिर बताई गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिनव देशमुख ने चेतावनी दी है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी ओर कुछ निवासियों ने दावा किया कि वह कई दशकों से यहां रह रहे थे और उनके पास हाउस टैक्स, वाटर टैक्स तथा बिजली कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज भी हैं। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ईद से ठीक पहले की गई कार्रवाई ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

हालांकि इन दावों और मानवीय पक्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिर अवैध कब्जों के खिलाफ हर कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? चाहे देश का कोई भी राज्य हो, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन पर हमला करना अब एक तथ्यमुदा रणनीति जैसा दिखाई देता है। इससे साफ है कि कुछ तत्व कानून व्यवस्था को बिगाड़कर सरकारी कार्रवाई को रोकना चाहते हैं। मुंबई जैसे संवेदनशील और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर में इस तरह की हिंसा न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और शहरी व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चुनौती भी है।

बंगाल के चुनाव नतीजों से उपजा नया विमर्श

राज किशोर

हालिया चुनाव परिणामों ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दिशा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वहां के सामाजिक मनोविज्ञान को लेकर एक नए विमर्श को जन्म दिया है। अक्सर तर्क दिया जाता रहा है कि बंगाल की वैचारिक भूमि पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसे आज हिंदुत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है, की जड़ें नहीं हैं और यह उत्तर या पश्चिम भारत से आयातित एक राजनीतिक विचार है। यदि तटस्थ विश्लेषण किया जाए, तो एक भिन्न तस्वीर उभरती है। सामान्यतः माना जाता है कि हिंदुत्व शब्द और उसके व्यापक अर्थों की अवधारणा सावरकर ने स्थापित की, पर उनसे लगभग तीन दशक पहले 1892 में बंगाली विद्वान चंद्रनाथ बसु ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व हिंदुर प्राकृत इतिहास में इसे परिभाषित किया था। बसु के लिए यह कोई संकीर्ण धार्मिक आग्रह नहीं, बल्कि व्यापक सभ्यतागत और सांस्कृतिक आत्मबोध था। उन्होंने विविधता के भीतर सांस्कृतिक निरंतरता को समाज की बड़ी शक्ति माना।

यह वह समय था, जब बंगाल में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक चेतना आकार ले रही थी और समाज सुधारक अपनी परंपराओं तथा जड़ों की और लौटकर नई पहचान गढ़ने का प्रयास कर रहे थे। बंकिम के आनंदमठ ने आधुनिक राष्ट्र की कल्पना केवल एक भूभाग के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति के प्रतीक रूप में की। आनंदमठ का ‘वंदे मातरम्’ अनुशीलन समिति जैसे संगठनों से जुड़े युवाओं के लिए प्रतिरोध का प्रेरणा स्रोत बन गया। इसी वैचारिक मंथन को स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद ने व्यापक आयाम दिए। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को आत्मविश्वास और आधुनिकता के साथ प्रस्तुत किया। जबकि महर्षि अरविंद ने अपने ‘उत्तरवादा अभिभाषण’ में सनातन धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। स्वतंत्रता के बाद यह विमर्श राजनीतिक स्वरूप में तब सामने आया, जब डॉ. रबिया प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ को स्थापना की। डॉ. मुखर्जी ने बंगाल की बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना को राष्ट्रीय अखंडता और राजनीतिक संगठन के साथ जोड़ने का प्रयास किया।

बंगाल पुनर्जागरण की परंपरा में ब्रह्म समाज, रवींद्रनाथ की सार्वभौमिक मानवीय दृष्टि, सामाजिक सुधार आंदोलनों और बाद के वामपंथी विचारों का भी गहरा प्रभाव रहा है।

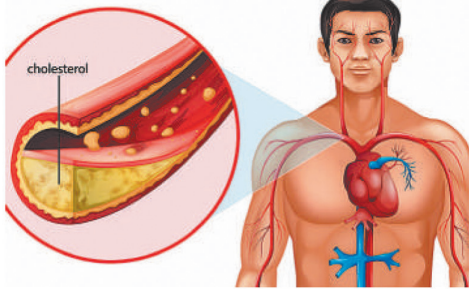
अनेक इतिहासकारों व विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल की अस्मिता बहुस्तरीय रही है, जिसमें धार्मिक–सांस्कृतिक चेतना के साथ उदारवाद, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष राजनीति को परंपराएं भी शामिल रही हैं। अतः वर्तमान राजनीतिक बदलाव को केवल सांस्कृतिक पुनरुत्थान के रूप में देखना सरलीकरण होगा।

स्वतंत्रता के बाद के दशकों में लंबे वामपंथी शासन और बाद में क्षेत्रीय राजनीति के दौर में ‘बंगाली अस्मिता’ को एक विशेष राजनीतिक व सांस्कृतिक ढांचे में परिभाषित किया गया। इस दौरान दुर्गा पूजा, काली पूजा और अन्य पारंपरिक उत्सवों को सिर्फ सांस्कृतिक आयोजनों के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी अवधि में यह धारणा मजबूत हुई कि बंगाली अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद परस्पर विरोधी विचार हैं। हालिया चुनाव परिणाम इस धारणा को चुनौती देते हैं। चुनाव के दौरान ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक अभिव्यक्ति के बीच संबंध अधिक स्पष्ट दिखाई दिया। नंदीग्राम जैसे क्षेत्रों में, जहां कभी भूमि और कृषि अधिकारों के संघर्ष प्रमुख थे, वहां अब सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी चर्चा के केंद्र में दिखा।

इससे यह प्रतीत होता है कि बंगाल का एक बड़ा वर्ग अब बंगाली अस्मिता और भारतीय सांस्कृतिक चेतना के बीच विरोध नहीं देखता। कृतिवास रामायण, चंडी दात और शक्ति उपासना जैसी परंपराएं लंबे समय से बंगाल के सामाजिक जीवन का हिस्सा रही हैं। वर्तमान राजनीति में इन प्रतीकों की बढ़ती उपस्थिति को समाज का एक वर्ग अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में देख रहा है। वही आलोचकों का मानना है कि यह ध्ववीकरण को भी जन्म दे सकता है।

यही कारण है कि बंगाल का वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन को केवल चुनावी घटना नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे इतिहास, सांस्कृतिक स्मृतियों, सामाजिक बदलावों और समकालीन राजनीति की जटिल अंतःक्रिया काम करती दिखती है। नए राजनीतिक संकेत बताते हैं कि राज्य का समाज अपनी विभिन्न ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धाराओं के बीच नए संतुलन की तलाश में है। यह प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी, इसका अंतिम उत्तर भविष्य की राजनीति और समाज ही तय करेंगे।

इस तरह कम करें कोलेस्ट्रॉल



मेडिकल साइंस के इस तथ्य से आप शायद अवगत ही होंगी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बढ़ने से हाई ब्लडप्रेशर और और अन्य हृदय रोगों के होने का जोखिम बढ़ जाता है, लेकिन कुछ बातों पर अमल करके आप बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर इसे नियंत्रित कर सकती हैं..

अनहेल्दी फैट से दूर

अनहेल्दी फूड के स्थान पर अपने खानपान में साबुत अनाज, ताजे फल और सब्जियां, फिश, ऑयल ऑयल, लहसुन, बादाम और अखरोट को शामिल करें।

काँफी कम

क्या आपको पता है कि प्रतिदिन तीन से छह कप काँफी पीने से आपके कोलेस्ट्रॉल में आठ से 10 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

एक्सरसाइज है गुड

हफ्ते में एरोबिक एक्सरसाइज के 30 मिनट के चार सेशन से आपके हाई-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (एचडीएल) के स्तर में इजाफा होगा। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है।

वजन पर नियंत्रण

वजन अधिक होने या मोटापे से ग्रस्त होने से आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ जाता है। इसलिए समय-समय पर अपना वजन चेक करती रहें।

ओम शांति शांति

शोधकर्ताओं के अनुसार तनाव व दबाव की स्थितियों में जो लोग शत्रुतापूर्ण या आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उनका एचडीएल स्तर कम होता है। वहीं जो लोग विपरीत स्थितियों में अपने क्रोध को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, उनका एचडीएल स्तर ऊँचा रहता है।

सेम और दाल भी घटाते है कोलेस्ट्रॉल

दिन में कम से कम एक बार भोजन में सेम, मटर या दाल खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहता है और हृदय की बीमारियों का खतरा कम होता है। सेंट माइकल हॉस्पिटल के चिकित्सक सिवेनपाइपर ने कहा कि दिन में एक समय भोजन में दाल खाने से पांच प्रतिशत तक कोलेस्ट्रॉल कम होता है। भोजन में दाल को शामिल करना हृदय के लिए फायदेमंद रहता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा पांच से छह प्रतिशत तक कम होता है। दालों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स (पाचन क्रिया के दौरान भोजन सामग्री का टूटना) का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है और इनमें अतिरिक्त प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को घटाने की क्षमता होती है। सिवेनपाइपर ने मेटा एनालाइसिस समीक्षा के तहत 1,037 लोगों पर अध्ययन किया। अध्ययन में पता चला कि पुरुषों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर महिलाओं की अपेक्षा कम होता है। इसका कारण महिलाओं का खान-पान में उचित ध्यान न देना हो सकता है। यह अध्ययन पत्रिका कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित हुई है।

पेनकिलर है हानिकारक

जीवन में बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें पेनकिलर दवाओं का सेवन करना पड़ता है। विशेषत आस्टियो-आर्थराइटिस के मरीजों को अधिक मात्रा में पेनकिलर दवाओं का सेवन करने की आदत हो जाती है। ऐसे मरीजों को यदि हृदय रोग भी हो तो ये दवाएं उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अधिक मात्रा में या पेनकिलर का अधिक सेवन हमारे गुर्दों को क्षतिग्रस्त कर सकता है।



आधुनिक जीवन शैली की तेज रफ्तार एवं भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का विषय बहुत पीछे रह गया है और नतीजा यह निकला की आज हम युवावस्था में ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, गटिया, थायरॉइड जैसे रोगों से पीड़ित होने लगे हैं जो कि पहले प्रोढ़ावस्था एवं व्रद्धावस्था में होते थे और इसकी सबसे बड़ी वजह है खान पान और रहन सहन की गलत आदतें, आओ हम सेहत के इन् नियमों का पालन करके खुद भी स्वस्थ रहे तथा परिवार को भी स्वस्थ रखते हुए अन्य लोगों को भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूक करें ताकि एक स्वस्थ एवं मजबूत समाज और देश का निर्माण हो,वयोंकि कहा भी गया है-पहला सुख निरोगी काया।

स्वस्थ शरीर है सबसे बड़ा खजाना

भोजन हो संतुलित

घी, तैल से बनी चीजें जैसे पड़ी,परांटे,छोले भटूरे,समोसे कवोड़ी, जंक फूड, चाय,काँफी ,कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन सेहत के लिए घातक है इनका अधिक मात्रा में नियमित सेवन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, मोटापा एवं हार्ट डिजीज का कारण बनता है तथा पेट में गैस,अल्सर, ऐसीडिटी, बार बार दस्त लगना, लीवर खराब होना जैसी तकलीफें होने लगती हैं इनकी बजाय खाने में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, छाछ , अंकुरित अनाज और सलाद को शामिल करना चाहिए जो की विटामिन,खनिज लवण,फाइबर,एव जीवनीय तत्वों से भरपूर होते हैं और शरीर के लिए बहुत कायदेमंद होते हैं। चीनी एवं नमक का अधिक मात्रा में सेवन ना करें,ये डायबिटीज,ब्लड प्रेशर,हृदय रोगों का कारण हैं । बादाम, किशमिश, अजीर, अखरोट आदि मेवा सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं इनका सेवन अवश्य करें पानी एवं अन्य लिखिड जैसे फलों का ताजा जूस,दूध,दही,छाछ,नींबू पानी,नारियल पानी का खूब सेवन करें,इनसे शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती,शरीर की त्वचा एवं चेहरे पर चमक आती है,तथा शरीर की गंदगी पसीने और पेशाब के द्वाारा बाहर निकल जाती है।

व्यायाम का करें नियमित अभ्यास

सुर्योदय से पहले उठकर पार्क जाएं,हरी घास पर नंगे पैर घूमें, दौड़ लगाएं, वाक करें, योगा, प्राणायाम करें, इन उपायों से शरीर से परीना निकलता है,मांस पेशियों को ताकत मिलती है,शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, अनेक शारीरिक एवं मानसिक रोगों से बचाव होता है,पूरे दिन भर बदन में चुस्ती फुर्ती रहती है,भूख अच्छी लगती है इसलिए नियमित रूप से व्यायाम अवश्य करें।



नींद भी है जरूरी

नेब्रस्का लिंकन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि ठीक से सो नहीं पाने के कारण आपका रोजमर्रा का कामकाज प्रभावित हो सकता है। साथ ही ज्यादा खाना खाने की प्रवृत्ति पनप सकती है। यह बच्चे और वयस्क, दोनों पर लागू होता है। वहीं नींद खराब होने के बाद, हार्मोन कट्रोलिंग सिस्टम भी प्रभावित होता है, इ स से भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है, और अधिक भोजन, ऊर्जा की कमी को पूरा करने में सक्षम नहीं है। दिन में जो भी आप खाते हैं यह सभी कारक भोजन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। नेब्रस्का लिंकन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता एलिसा-लिंकन और टीमोथी डी नेल्सन का कहना है कि डॉक्टरों को नींद और खाने के प्रति जागरूक होना चाहिए। नींद सक्रिय रूप से आहार-व्यवहार को बदल देती है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। मोटापे



से मधुमेह, हृदय रोग जैसी घातक बीमारी होने का खतरा बना रहता है। दूसरी ओर, इस बारे में लेखक का कहना है कि अत्यधिक भोजन करना व बाधित नींद को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भोजन का सेवन जैविक, संज्ञात्मक, भावनात्मक और पर्यावरणीय कारकों से प्रेरित है। इसमें लुथल और नेल्सन का तर्क है कि इन कारकों से सोने की प्रवृत्ति प्रभावित है। नींद प्रभावित होने के चलते वयस्कों और बच्चों दोनों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि लोग इसके लिए जागरूक हों, उन्हें खाने की गुणवत्ता और मात्रा का भी ख्याल रखना चाहिए। यह शोधपत्र एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है।

ये उपाय करें

सोने का कमरा साफ सुथरा,शांत एवं एकांत में होना चाहिए,रात को अधिकतम 10-11 बजे तक सो जाना और सुबह 5-

टेंशन को कहें बाय बाय

रोज मर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याों के लिए चिंतन करना सही है चिंता करना नहीं,चिंता तो फिर भी मरने के बाद शरीर को जलाती है किन्तु लगातार अनावश्यक चिंता जीते जी शरीर को जला देती है इसलिए तनाव होने पर भाई,बंधु एवं विद्यास पात्र मित्रों से सलाह मशरा करें यदि समस्या फिर भी ना सुलझे तो विशेषज्ञ से राय लें।

दिल की बीमारियों से दूर रखता है अखरोट

हालिया शोध में पता चला है कि रोजाना अखरोट खाने से डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। कर्नेविकट स्थित येल ग्रिफिन प्रिवेशन रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं के मुताबिक, रोज 56 ग्राम अखरोट के सेवन से अधिक वजन वाले वयस्कों के शरीर की अंतःरिक प्रक्रिया में सुधार आता है। इस शोध में 30 से 75 साल के 46 वयस्कों को शामिल किया गया था।



बीमारी से बेहतर है बचाव



कहते हैं कि बीमारी से बेहतर है बचाव। दिल को स्वस्थ रखने के संदर्भ में कुछ सुझावों पर अमल करें..

- नियमित रूप से अपने शरीर की क्षमता के अनुसार व्यायाम करें। व्यायाम भी दिल को सेहतमंद रखने में कारगर है।
- डॉक्टर से परामर्श लेकर आप कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम भी कर सकते हैं।
- टहलना भी अच्छ व्यायाम है। शरीर की क्षमता के मद्देनजर नियमित रूप से टहलें।
- जो लोग पहले से ही डाइबिटीज, हाई ब्लडप्रेशर से ग्रस्त हैं, उनमें हृदय संबंधी समस्याएं होने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। इसलिए डाइबिटीज से ग्रस्त लोगों को नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर की जांच करनी चाहिए। इसी तरह हृदय रोगों से ग्रस्त लोगों को भी ब्लडप्रेशर चेक करते या कराते रहना चाहिए।
- अगर ब्लडशुगर और ब्लड प्रेशर अनियंत्रित है, तो शीघ्र ही अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
- डॉक्टर से परामर्श लेकर एक अंतराल पर रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच कराते रहें।
- तंबाकू का सेवन न करें।
- अत्यधिक नमकीन खाद्य पदार्थों को खाने से परहेज करें। नमक कम मात्रा में लें।

तेल का महत्व

लोगों को खाने के तेल पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर सही प्रकार और सही मात्रा में तेल का इस्तेमाल किया जाए, तो दिल संबंधी बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। इस संदर्भ में राइस ब्रैन तेल अत्यंत लाभप्रद है। इस तेल को चावल के भूसे में से निकाला जाता है। इसके अलावा सरसों का तेल, जैतून और सोयाबीन का तेल भी दिल की सेहत के लिए लाभप्रद है।

वजन कम करना है तो खाइए प्रोजन फूड

वजन कम करना चाहते हैं तो अपने फ्रीज में झाक कर देखिए। डॉक्टरों का कहना है कि प्रोजन फूड खान से मोटापे को कम करने में मदद मिलती है। विशेषज्ञों का दावा है कि कम कैलोरी का फोजन फूड खाने से कमर को फैलने से रोक जा सकता है क्योंकि इस प्रकार का भोजन कैलोरी के हिसाब से नियंत्रित होता है । लोयाला यूनिवर्सिटी हेथ्य सिस्टम में पोषाहार और वजन नियंत्रण प्रबंधन की विशेषज्ञ जेसिका बार्टफील्ड ने बताया, ‘कम कैलोरी के भोजन से नियंत्रित मात्रा में कैलोरी ली जाती है जिससे वजन को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।’ बार्टफील्ड का कहना है कि अधिकतर लोग कम कैलोरी का भोजन लेते हैं जो प्रतिदिन 1000 से 1800 कैलोरी प्रतिदिन होता है। यह वजन, उम्र, कद और लिंग पर निर्भर करता है।

रैसिपी



विधि

एक कड़ाही में घी डालकर गर्म करें और रवा डालकर सुनहरा होने तक भूनें। डेढ़ कप पानी के साथ दूध मिलाएं और एक उबाल दें। फिर उसे भूने हुए रवा (सूजी) में मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। किशमिश, बादाम, केसर, इलायची पाउडर और चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। गरमागरम सर्व करें।

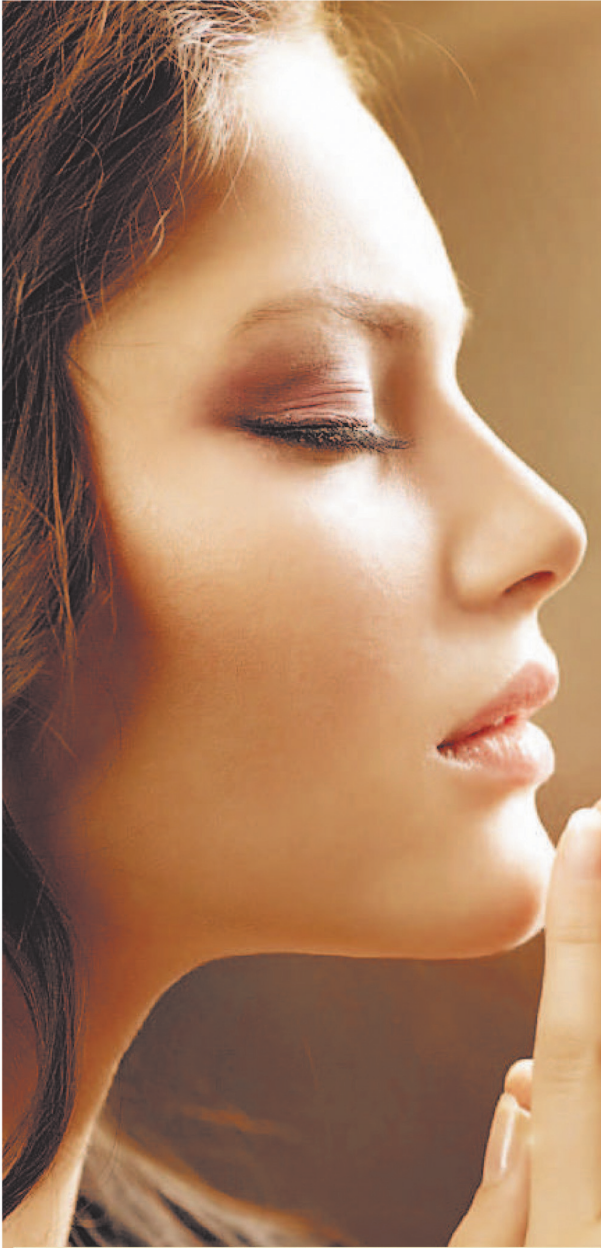
कितने लोगों के लिए : 4



विधि

गवार की फली के किनारे निकालकर, अगर इसमें कोई धागा है तो वो भी निकाल दें, अच्छी तरह धो लें और एक साफ कपड़े से इसका पानी पोंछ लें। फली को इच्छानुसार छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। एक कड़ाही में मध्यम आंच पर तेल गरम करें। इसमें जीरा और अजवाइन डालें, कुछ देर के लिए भूनें और फिर हींग डालें। आंच को धीमा करके हल्दी डालें और फिर गवार के टुकड़े डाल दें। इस सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं। नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें, और फिर से सब्जी को एक मिनट के लिए चलाएं। गवार के गलने तक ढक कर पकाएं। इसमें लगभग 12–15 मिनट का समय लगता है। जब सब्जी गल जाए तो इसमें अमचूर डालकर सब्जी को दो मिनट के लिए भूनें। रोटी, पूरी, पराठा या फिर दाल चावल किसी के भी साथ गरम परोसें।

प्रार्थना से भी दूर होता है तनाव



नोएटिक थेरेपी क्या है

नोएटिक (मंत्रों, संगीत, स्पर्श और प्रार्थना) थेरेपी वह थेरेपी होती है जिसमें बिना दवाई, उपकरण और सर्जरी के इलाज किया जाता है। कई मरीजों पर नोएटिक थेरेपी का इस्तेमाल करने से पाया गया है कि वह, जो सिर्फ दवाई लेते हैं, उनके मुकाबले इनके 30 प्रतिशत ज्यादा सही होने की संभावना होती है साथ ही इन लोगों में एक आशासन इस बात का भी होता है कि ये मरीज लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ते।

जीवनशैली पर पूजा का प्रभाव

नियमित रूप से पूजा और प्रार्थना करने से मन में सकारात्क ऊर्जा बढ़ती है। और प्रार्थन करने वाला व्यक्ति भीतर से अच्छ और बेहतर महसूस करता है। इससे जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। आजकल अनियमित जीवनशैली कई रोगों की मुख्य वजह है। जब आप पूजा व प्रार्थना को अपने जीवन में एक आदत के तौर पर शामिल करते हैं तो निश्चित ही आप अपने अंदर अच्छ बदलाव महसूस करेंगे। विशेषज्ञों की मानें तो पूजा और सपीत व्यक्ति में बढ़ रहे दबाव का स्तर कम करते हैं। इसका मतलब है ये गतिविधियां जीवन में संतुलन बनाए रखती हैं। प्रार्थना का सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए जरूरी है कि उसे दिल से किया जाए। नियमित योग करने वाले लोग जो हमेशा फिट रहते हैं वह भी एक किस्म की पूजा प्रार्थना ही कर रहे होते हैं।

प्रार्थना के अन्य लाभ

- प्रार्थना करने से मन स्थिर और शांत रहता है। क्रोध पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है।
- इससे स्मरण शक्ति और चेहरे की चमक बढ़ती है।
- प्रार्थना से मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, जिससे मन निरोगी बनता है।
- शोध में पाया गया है नियमित तौर पर ईश्वर का ध्यान करने और प्रार्थना करने से रक्त संचार दुरुस्त रहता है।
- सामूहिक तौर पर प्रार्थना करने से व्यक्ति के मन में एकता का भाव बढ़ता है और अकेलापन दूर होता है।
- धार्मिक स्थल तक पैदल चल कर जाने से व्यायाम भी हो जाता है।
- प्रतिदिन प्रार्थना करने से व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, जिससे एकाग्रता आती है।

दोनों माता-पिता आईएएस हैं तो आरक्षण क्यों

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षण और सामाजिक गतिशीलता के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को मिलने वाले आरक्षण लाभ से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि जिन परिवारों ने शिक्षा और आर्थिक रूप से प्रगति कर ली है, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ मामले को सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर दोनों माता-पिता आईएएस अधिकारी हैं तो फिर उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रशांक रतनु ने कहा कि लोगों को उनकी सैलरी की वजह से नहीं, बल्कि उनके सामाजिक दर्जे के आधार पर बाहर किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप-ए कर्मचारियों को बाहर किया गया है और ग्रुप-बी कर्मचारियों को भी बाहर किया जाता है।

महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा की दो रिक्त सीटों के लिए उप चुनाव 18 जून को

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा की दो रिक्त सीटों के लिए उप चुनाव 18 जून को कराने की घोषणा की है।ये दोनों रिक्तियां क्रमशः श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार और श्री सी वी षण्मुगम के त्यागपत्र से उत्पन्न हुई हैं। महाराष्ट्र से निर्वाचित श्रीमती सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा की सदस्यता से 6 मई को और श्री षण्मुगम ने 7 मई को इस्तीफा दिया था इनका कार्यकाल क्रमशः 4 जुलाई 2028 और 29 जून 2028 को समाप्त होना था।नूनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी कार्यक्रम के अनुसार इन दोनों राज्यों से रिक्त सीटों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कराये जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी और नाम 11 जून तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 18 जून को प्रातः 9ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक रखा गया है।

आरजेडी के पोस्ट पर बिहार की राजनीति में घमासान

नईदिल्ली। आरजेडी ने जेडीयू नेताओं की सूटकेस वाली तस्वीर शेयर कर नया विवाद खड़ा कर दिया है. जेडीयू ने इसे पारंपरिक विदाई उपहार बताया.बिहार में एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है. राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें जेडीयू के नेता संजय कुमार झा, राजीव रंजन सिंह उर्फ ?ललन सिंह और दिनेश प्रसाद सिंह नजर आ रहे हैं. तस्वीर में जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह, संजय झा को एक सूटकेस देते हुए दिखाई दे रहे हैं. आरजेडी ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मामला सिर्फ़ थैली (बैग) तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब बात सूटकेस और बोरे तक पहुंच गई है. इस पोस्ट ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. इसकी वजह यह है कि यह पोस्ट पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के उस आरोप के ठीक बाद आया है, जिसमें उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) के नेताओं पर थैली कल्चर (पैसे के लेन-देन की संस्कृति) को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. आनंद मोहन ने आरोप लगाया था।

कोलकाता से पाक जासूस गिरफ्तार, सामने आए खुलासे

कोलकाता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भारत विरोधी गतिविधियों और कथित जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता के एक निवासी को गिरफ्तार किया है. एजेंसी का आरोप है कि आरोपी पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी पहुंचाने में शामिल था. इस गिरफ्तारी को देश विरोधी साजिश से जुड़े बड़े नेटवर्क की जांच में अहम माना जा रहा है.गिरफ्तार आरोपी की पहचान जफर रियाज उर्फ रिजवी के रूप में हुई है. जांच एजेंसी के मुताबिक उसके खिलाफ पहले से लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था और उसे अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया भी चल रही थी. एनआईए ने उसे भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधिअधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है.जांच में सामने आया है कि जफर की शादी एक पाकिस्तानी नागरिक से हुई थी और उसके बच्चे भी पाकिस्तान की नागरिकता रखते हैं. एजेंसी के अनुसार वह वर्ष 2005 से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा करता रहा था।

टीम बदलने लगीं मायावती, आकाश आनंद के लिए तैयार हो रहा प्लान



लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने अब अपने सियासी अभियान को धार देना शुरू कर दिया है. दिल्ली प्रवास से लौटते ही बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी कई नेताओं से मुलाकात कर फीडबैक लेने के बाद संगठन में बड़ा फेरबदल भी शुरू कर दिया है. लखनऊ में पार्टी संगठन की होने वाली बैठक में मायावती मिशन-यूपी के लिए अपना रोडमैप रखेंगी. मायावती ने प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ जिला संगठनों के नेताओं को भी बैठक में बुलाया है, जिसमें वो जमीनी हकीकत को समझने के साथ-साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगी. ऐसे में बसपा प्रमुख कई मंडलों के प्रभारियों में बदलाव किए जाने की भी संभावना है.उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा लगातार कमजोर होती जा रही है. ऐसे में 2027 का चुनाव बसपा के लिए अत्यंत सियासी वजुद को बचाए रखने का है. यही वजह है कि बसपा प्रमुख अगले विधान सभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने में जुटी है।

सौजन्य मुलाकात

मुर्मु, राधाकृष्णन और मोदी से मिले शुभेन्दु अधिकारी

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने शुक्रवार को यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु , उप राष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और राष्ट्रपति को विश्वास दिलाया कि उनकी पश्चिम बंगाल की पिछली यात्रा की कष्टप्रद स्मृतियों को मिटाने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राजधानी दिल्ली आये श्री अधिकारी ने सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट में इन मुलाकातों की जानकारी दी। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उन्होंने तुण्मूल काग्रेस सरकार के कार्यकाल में श्रीमती मुर्मु के सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संधाल सम्मेलन में शामिल होने के दौरान हुए राजनीतिक विवाद का उल्लेख किया। इस यात्रा के दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या उनका कोई मंत्री राष्ट्रपति के स्वागत के लिए नहीं आया था और सम्मेलन के आयोजन स्थल को भी अंतिम मौके पर बदल दिया गया था। राष्ट्रपति ने इस घटनाक्रम पर गहरी निराशा व्यक्त की थी।

श्री अधिकारी ने पोस्ट में कहा,- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मैं हृदय से आभारी और सम्मानित महसूस करता हूँ कि उन्होंने मुझे दर्शन देने का अवसर प्रदान किया।पश्चिम बंगाल की जनता आपके प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे राज्य की अपनी अगली यात्रा के दौरान, पश्चिम बंगाल की नई सरकार आपकी पिछली यात्रा की उन कष्टप्रद स्मृतियों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी-जहाँ दुर्भाग्यवश, उस समय की तत्कालीन सरकार ने आपके गरिमामय पद और स्तर को कमतर दिखाने का प्रयास किया था। पश्चिम बंगाल यह सुनिश्चित करेगा कि आपको वह सर्वोच्च सम्मान, गरिमा और आदर प्रदान किया जाए, जिसके आप हमारे महान राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख के रूप में पूर्णतः हकदार हैं। श्री मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के



मंत्र पर पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास और औद्योगिक पुरस्कार का आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा :- आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर मैं स्वयं को सम्मानित और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी, यानी मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री के साथ यह मेरी पहली आधिकारिक मुलाकात थी। मैं प्रधानमंत्री का उनकी शुभकामनाओं के लिए, और सबसे बढ़कर, हमारे राज्य की प्राप्ति के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी सार्थक चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री ने %सबका साथ, सबका विकास% के अपने विजन पर फिर से जोर दिया और दोहराया कि पश्चिम बंगाल का विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है। मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पश्चिम बंगाल को वर्षों की जड़ता से बाहर निकालने और उसे आर्थिक विकास, औद्योगिक पुनरुद्धार और युवा सशक्तिकरण की तेज रफ्तार वाली राह पर मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद, मार्गदर्शन और केंद्रीय सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्र के आशीर्वाद और लोगों के भरोसे के साथ, हम पश्चिम बंगाल में %डबल-इंजन प्रोथ%, पारदर्शी शासन और समा विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जय हिंद वंदे मातरम। उप राष्ट्रपति से भेंट करना मेरे लिए एक परम सौभाग्य की बात है।

स्टेल प्रमुख समाचार

ऑस्ट्रेलिया से सीरीज के लिए पाकिस्तान की वनडे टीम घोषित

कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी। टीम की कप्तान एक बार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को सौंपी गई है। इस टीम में कई बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है। बाबर आजम, शादाब खान, नसीम शाह और हातिस रऊफ को वनडे टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा सुफियान मुकीम की भी वापसी हुई है, जो बांग्लादेश के खिलाफ पिछली सीरीज का हिस्सा नहीं थे। वहीं, अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान की टीम में तीन ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिन्होंने अभी तक वनडे डेब्यू नहीं किया है। अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास और रोहैल नजीर पहली बार वनडे टीम का हिस्सा बने हैं। हालांकि ये तीनों खिलाड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं। पीसीबी के मुताबिक, उस्मान खान बीमारी की वजह से चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

ऑस्ट्रेलिया टीम 23 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मुक़ाबला दो और चार जून को लाहौर में होगा। दोनों टीमों के बीच पिछली वनडे सीरीज 2024 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी, जिसमें पाकिस्तान ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। यह 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की पहली वनडे सीरीज जीत थी।

टीम: शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), सलमान अली आंगा (उपकप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, हातिस रऊफ, माज सदाकत, मुहम्मद गाजी गौरी (विकेटकीपर), रोहैल नजीर (विकेटकीपर), नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, शादाब खान, शामिल हुसैन, सुफियान मुकीम।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

संसेक्स 232 अंक उछला निफ्टी 23,719 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। घरेलू बाजारों को रुपये में आई मजबूती और बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं के शेयरों में खरीदारी से समर्थन मिला। सत्र के अंत में निफ्टी 50 में 64.60 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 23,719.30 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, संसेक्स 231.99 अंक चढ़कर 75,415.35 पर बंद हुआ। भारतीय रुपये ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत प्रदर्शन किया। दिन के कारोबार में रुपया 51 पैसे की बढ़त के साथ 95.69 के इंट्राडे हाई तक पहुंचा। हालांकि, कारोबार खत्म होने पर यह 96.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में ट्रेड, श्रेयम फाइनेंस और एक्सिस बैंक जैसे शेयर सबसे ज्यादा बढ़त के साथ प्रमुख लाभ में रहे। इन शेयरों में खरीदारी का रझान देखने को मिला, जिससे इंडेक्स को सपोर्ट मिला।

दालों के आयात में 34 प्रतिशत की भारी गिरावट

नई दिल्ली। देश में दालों के मजबूत घरेलू उत्पादन और कमजोर मांग के चलते वित्त वर्ष 2025-26 में दालों के आयात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में दालों का आयात मूल्य के आधार पर 34 प्रतिशत घटकर 3.63 अरब डॉलर रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह रिकॉर्ड 5.54 अरब डॉलर था। मात्रा के लिहाज से भी दाल आयात 12 प्रतिशत घटकर 60 लाख टन रह गया, जो एक वर्ष पहले 73.4 लाख टन था। व्यापार सूत्रों के मुताबिक वैश्विक बाजार में दालों की कीमतों में भारी गिरावट और घरेलू स्तर पर पर्याप्त उत्पादन के कारण आयात में कमी आई है। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी तनाव का अब तक दाल आयात पर बड़ा असर नहीं पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में मानसून की स्थिति घरेलू उत्पादन और आयात की जरूरत तय करेगी।

होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में

टी टी राम मोहन

ईरान संकट में एक बड़ा रहस्य है और वह है तेल बाजारों का व्यवहार। कहा जा रहा है कि यह इतिहास में तेल बाजारों में मची सबसे बड़ी उथलपुथल है। इसके बावजूद बाजार तेल की कीमतों को उस स्तर से काफी नीचे आंक रहे हैं जिसे विश्लेषक बुनियादी कारकों के आधार पर उचित मानते हैं। या तो विश्लेषक बेवकूफ हैं या फिर बाजार बहुत अदृग्दर्शी साबित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका पता चल जाएगा।

फरवरी के अंत में ईरान में लड़ाई छिड़ने के बाद तेल कीमतें शुरुआत में 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रहीं। विशेषज्ञों ने माना कि यह लड़ाई चार-छह सप्ताह से अधिक नहीं चलेगी और ऐसे में विश्व अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक असर नहीं होगा।

यह धारणा गलत थी कि संघर्ष के चार सप्ताह या कम समय में समाप्त होने से तेल

आपूर्ति में व्यवधान भी समाप्त हो जाएगा। जैसा कि द इकॉनमिस्ट ने 30 अप्रैल के अपने अंक में इंगित किया है, तेल कुओं में उत्पादन को तुरंत शुरू नहीं किया जा सकता है। उत्पादन को सामान्य स्तर पर लौटने में कई सप्ताह का वक्त लगता है। ये टैंकर जो अन्य मार्गों पर चले गए हैं उन्हें फिर से फारस की खाड़ी में लौटना पड़ता है। इसमें काफी समय लगता है। वे रिफाइनरी को कच्चे तेल की आपूर्ति के अभाव में बंद हो पाई थीं उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता है। ऐसे में यह तय था कि तेल आपूर्ति में व्यवधान लंबा खिंचने वाला है।

तेल बाजार और उन पर भरोसा करने वाले विशेषज्ञ गलत साबित हुए। लड़ाई चार-छह हफ्ते में खत्म नहीं हुई। वह लड़ाई 10 सप्ताह बाद भी चल रही है। चिंता की बात यह है कि क्या तेल बाजार ईरान के हालात को सही ढंग से दर्शा पर रहे हैं या नहीं। विश्लेषक



ऐसा नहीं सोचते। तेल बाजारों की सबसे बड़ी विफलता यह रही कि उन्होंने ईरान की होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की क्षमता और इच्छा का अनुमान नहीं लगाया।

ऐसा लगता है कि उन्होंने यह मान लिया था कि क्योंकि यह पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए अब भी नहीं होगा। जबकि ईरान के नेताओं ने बहुत स्पष्ट चेतावनियां दी थीं कि अमेरिका के हमले पर देश कैसे जवाब देगा। इन चेतावनियों को न तो अमेरिकी प्रशासन ने गंभीरता से लिया और न ही तेल बाजारों ने।

द इकॉनमिस्ट का अनुमान है कि होर्मुज

रिलायंस पावर को जनवरी-मार्च तिमाही में 494 करोड़ रु. का घाटा

नई दिल्ली। रिलायंस पावर ने जनवरी-मार्च तिमाही में 494 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने पिछले वर्ष की समान तिमाही में 125.57 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया था। रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय घटकर 1,946.33 करोड़ रुपए रह गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 2,065.64 करोड़ रुपए थी। कंपनी को वित्त वर्ष 2025-26 में 336.89 करोड़ रुपए का घाटा हुआ जबकि 2024-25 में इसने 2,947.83 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। वहीं कुल आय 8,257.04 करोड़ रुपए से घटकर 7,988.52 करोड़ रुपए रह गई। कंपनी के निदेशक मंडल ने पात्र संस्थागत खरीदारों को शेयर व उससे जुड़े साधनों और/या अन्य पात्र प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

थोक और खुदरा कीमतों के अंतर ने बढ़ाई परेशानी

नईदिल्ली। डीजल की थोक और खुदरा कीमतों में लगभग 40-42 रुपए प्रति लीटर के बड़े अंतर के कारण देशभर में कई थोक खरीदार पेट्रोल पंपों पर डीजल खरीदने पहुंच रहे हैं। इससे कुछ इलाकों में ईंधन की अस्थायी कमी और लंबी कतारों की स्थिति बन गई है। सरकार ने गुरुवार को बताया कि कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की मांग सामान्य से 20-30 प्रतिशत तक बढ़ गई है। दरअसल, तेल वित्पणन कंपनियों ने 1 मई को अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद थोक डीजल के दाम में 12 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। वहीं खुदरा डीजल की कीमतों में पिछले सप्ताह करीब 4 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई। दिल्ली में थोक डीजल लगभग 149 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि खुदरा कीमत 91.58 रुपए प्रति लीटर है।

विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के उसाहजनक संदेश 'हम समाधान के करीब हैं', 'यह जल्द ही समाप्त होगा' और इसी तरह की अन्य बातों का तेल बाजारों पर अपेक्षा से कहीं अधिक प्रभाव पड़ा है। यदि विश्लेषक सही हैं, तो विश्व अर्थव्यवस्था जल्द ही गंभीर संकट में पड़ सकती है। अब तक देखे गए तेल मूल्य स्तरों पर भी, विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। आईएमएफ का विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026) इस साल 'डॉलर प्रति बैरल मानता है। इसे वह अपना संदर्भ पूर्वानुमान कहता है। इस परिदृश्य में, वैश्विक वृद्धि 2024 के 3.4 फीसदी से घटकर 2026 में 3.1 फीसदी हो जाती है। यह आईएमएफ के जनवरी पूर्वानुमान से 0.2 प्रतिशत अंक कम है, जो ईरान संघर्ष शुरू होने से पहले किया गया था।

रायपुर को मिली बड़ी सौगात, लाखों लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत

कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कर इसे आम जनता को समर्पित किया। साथ ही 22.79 करोड़ रुपये की लागत से बने शंकर नगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और यह ओवरब्रिज उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कचना रेलवे फाटक में लंबे समय से जाम की समस्या बनी हुई थी, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ओवरब्रिज के शुरू होने से अब लोगों को सुगम, सुरक्षित और



निर्बाध यातायात सुविधा मिलेगी। इससे विशेष रूप से कचना, खम्हारडीह एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत इस परियोजना को साथ-साथ व्यापारी एवं व्यवसायियों को भी बड़ी सुविधा होगी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र

लिए खुशी का दिन है। जनता की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। अब यहां ट्रैफिक जाम और वाहनों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी। इससे कार्यालय, स्कूल-कॉलेज जाने वाले लोगों के साथ-साथ व्यापारी एवं व्यवसायियों को भी बड़ी सुविधा होगी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र

सरकार से प्राप्त निधि के माध्यम से इस ओवरब्रिज का निर्माण संभव हुआ है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस ब्रिज की लंबाई 787 मीटर एवं चौड़ाई 13 मीटर है तथा 48.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस ओवरब्रिज के बनने से रायपुर शहर की यातायात व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा समय की बचत भी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क, पुल और अन्य अधोसंरचना विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है, ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो

सकें। उन्होंने निर्माण कार्य में जुड़े अधिकारियों एवं एजेंसियों को बधाई देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने के साथ ही सीधे लोगों के बीच जाकर योजनाओं और विकास कार्यों का फीडबैक भी ले रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर वास्तविक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है।

एग्रोफॉरेस्ट्री और जनभागीदारी से हरित छत्तीसगढ़ का संकल्प: कश्यप

■ ‘सागौन की खेती से समृद्ध हुआ छत्तीसगढ़ का किसान, मिला 9.69 लाख का लाभ’

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए एग्रोफॉरेस्ट्री एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण का लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार की इसी दूरगामी पहल का एक बेहद सफल और प्रेरणादायी परिणाम बालोद जिले के किसान अनिल जाजू की सफलता के रूप में सामने आया है। नवा रायपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कश्यप ने ग्राम पलारी निवासी कृष्ण अनिल जाजू को उनकी निजी भूमि पर तैयार किए गए सागौन वृक्षों के एवज में 9.69 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर वन मंत्री श्री



केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के जोखिमों से उबारने के लिए वृक्ष आधारित कृषि प्रणाली अपनाने हेतु प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा कि एग्रोफॉरेस्ट्री किसानों के लिए दीर्घकालिक आय का मजबूत माध्यम बन रही है। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के जरिए जनभागीदारी से हरित छत्तीसगढ़ निर्माण को भी गति मिल रही है।

वन मंत्री ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से अब जनभागीदारी से पूरे प्रदेश को हरा-भरा बनाने की मुहिम को एक नई और अभूतपूर्व गति मिल रही है। 24 वर्षों की मेहनत का फल

मीठा मिला, किसान श्री अनिल जाजू की यह सफलता अन्य किसानों के लिए एक बेहतरीन केस-स्टडी है। वर्ष 2001 में अपनी 3.35 हेक्टेयर निजी भूमि पर सागौन के पौधे लगाए थे। लगभग 24 वर्षों तक देखरेख और संरक्षण के बाद वर्ष 2025 में अपनी 3.35 हेक्टेयर निजी भूमि पर सागौन के पौधे लगाए थे। उन्होंने वृक्ष कटाई नियम 2022 के तहत अनुमति लेकर सागौन वृक्षों की कटाई कराई। वन विभाग की देखरेख में कुल 173 सागौन वृक्षों की कटाई की गई, जिससे 949 नग लकड़ी प्राप्त हुई। इसका कुल आयतन 33.24 घनमीटर दर्ज किया गया। वन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर लकड़ी का क्रय किया गया।

निर्विवाद प्रकरणों का निराकरण करना अधिकारियों की जिम्मेदारी: शर्मा

रायपुर। हम सभी जनता के सेवक हैं और जनता के कार्य करना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसानों और ग्रामीणों के छोटे-छोटे कार्यों को संवेदनशीलता के साथ समय पर पूरा किया जाना चाहिए। राजस्व से जुड़े मामलों को लंबित नहीं रखना जाना चाहिए और निर्विवाद प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उक्त वक्तव्य उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के ग्राम खड़ौलकला में आयोजित सुशासन तिहार में दिए।

उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं, आवेदन प्राप्त किए तथा अनेक आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया।



उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का संवेदनशीलता और तय समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना हमारा परम धर्म है और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सुशासन का उद्देश्य है।

सुशासन तिहार शिविर में नि:शुल्क दस्तावेज सुविधा: उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया कि सुशासन तिहार शिविर में बी-1, खसरा और ऋण पुस्तिका जैसी

आवश्यक दस्तावेज नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने ग्राम सचिवों को निर्देशित किया कि पंचायतों में इसकी मुनादी कराई जाए ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिल सके और वे इसका लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख परिवारों को आवासों की स्वीकृति दी गई थी। उन्होंने बताया कि आज के शिविर में शामिल 26 ग्राम पंचायतों के 4 हजार से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है। उन्होंने आवास निर्माण में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि इसके निर्माण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एआई के प्रयोग से घर बैठे समस्या का शीघ्र निदान हुआ संभव: सोनमणि



रायपुर। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 अंतर्गत आदिम जाति विकास विभाग अंतर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आज राज्य स्तरीय एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस संगोष्ठी में पंचश्री अजय मंडावी की गरिमामयी उपस्थिति रही। आदिम जाति विकास विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पारदर्शिता, समय की बचत एवं घर बैठे समस्या का शीघ्र निदान संभव हुआ है। छत्तीसगढ़ जनजाति संग्रहालय एवं शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय में बड़े पैमाने पर

डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। बड़े पैमाने पर डिजिटल तकनीक के प्रयोग में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है। प्रमुख सचिव बोरा ने कहा कि एआई का प्रयोग पारंपरिक ज्ञान को संजोने, रिमोट एरिया में स्वास्थ्य सुधार, लघु वनोपजों एवं कृषि मंडियों के डिजिटलीकरण, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा, कौशल विकास, सरकारी योजनाओं की अधिक सुगमता से जानकारी एवं लाभ इत्यादि में किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनजातीय विकास में एआई का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परन्तु एआई मनुष्य की संवेदनशील मानसिकता की प्रतिकृति नहीं कर सकती है।

रायपुर। कृषि महाविद्यालय रायपुर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक तथा अविस्मरणीय रहा जब यहां इतिहास, वर्तमान एवं भविष्य का संगम देखने को मिला। कृषि महाविद्यालय, रायपुर के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिवार की तीन पीढ़ियां एकत्र हुईं जिनमें कृषि महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता एवं प्राध्यापक, वर्तमान कुलपति, कुलसचिव एवं प्राध्यापकगण और वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित थे। इस अवसर पर महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव समारोह, छात्र संघ शपथ ग्रहण, पूर्व अधिष्ठाता सम्मान तथा पूर्व छात्र सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया जिसके तहत महाविद्यालय के प्रथम बैच के तीन विद्यार्थियों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के खास मुकाम हासिल



करने वाले भूतपूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही महाविद्यालय के सात पूर्व अधिष्ठाताओं और इसी महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति, कुलसचिव तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का भी सम्मान किया गया।

सम्मान समारोह के पश्चात आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह में कृषि महाविद्यालय, रायपुर के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक

रंगा-रंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शक-दीर्घा का मन मोह लिया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कृषक सभागार में आज दोपहर आयोजित स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल थे। डॉ. चंदेल ने इस अवसर पर नवगठित छात्र संघ के पदाधिकारियों को पद सन्निधा एवं अनुशासन की शपथ दिलाई।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

स्मार्ट मीटर से बिजली खपत ज्यादा: दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि स्मार्ट मीटर के कारण बिजली की खपत से ज्यादा रीडिंग आ रही है। जनता परेशान है। इस माह लोगों का बिल तीन गुना तक बढ़कर आया है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश से स्मार्ट मीटर वापस लिया है। हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ से भी स्मार्ट मीटर वापस लिया जाये। उत्तरप्रदेश सरकार ने माना कि स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत ज्यादा आ रही है, योगी मंत्रिमंडल ने इसे बदलने का फैसला किया है, छत्तीसगढ़ में भी इसे वापस



लिया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हर जगह बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उनकी खपत वास्तविक खपत से अधिक बताई जा रही है, स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर की तुलना में बहुत तेजी से चल रहा है। बिजली उपभोक्ताओं का यह अधिकार है कि अपनी वास्तविक खपत को जान सके। चेक मीटर का प्रावधान पहले से ही था, लेकिन यह सरकार अपनी लूट पर परदेदारी करने के लिए चेक मीटर लगाने और मीटर चेक करवाने उपभोक्ताओं से 1000 और 1500 रुपए शुल्क लेने का प्रावधान कर दिया गया है, यदि मीटर में गड़बड़ी का आरोप उपभोक्ता लगा रहे हैं, तो उसे मुफ्त में चेक किया जाए, किसी भी तरह से अतिरिक्त शुल्क अनुचित है।

सरकार उर्वरकों की उपलब्धता पर श्वेत पत्र जारी करें : शुक्ला

रायपुर। खरीफ के लिए खाद उपलब्ध करवा पाने के मामले में सरकार ने ठोस प्रयास शुरू नहीं किया है। कृषि मंत्री केवल मीडिया में बयान देकर अपने कर्तव्य की पूर्ति समझ लिए हैं। सरकार ने अभी तक उर्वरकों की व्यवस्था के बारे में निश्चित बनी हुई है। अभी तक सरकार को किसानों की जरूरत के अनुसार सोसायटियों से मांग का डाटा एकत्रित कर सभी सोसायटियों में खाद पहुंचाना शुरू कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार बताये कि इस वर्ष कितने उर्वरकों की जरूरत का आंकलन किया गया तथा सरकार के पास कितनी उपलब्धता की व्यवस्था की गयी है? सरकार उर्वरकों की उपलब्धता पर श्वेत पत्र जारी करें।



बाजपा की सरकार आदतन किसान विरोधी है, पिछले खरीफ सीजन में खाद का संकट छत्तीसगढ़ के किसानों ने भोगा हैं, अब फिर वही स्थिति बन रही है, सरकार के संरक्षण में नकली खाद, अमानक खाद, नैनी यूरिया के नाम पर गुणवत्ताहीन खान लेने किसानों को मजबूर किया गया, ऐसे ही झूठे दावे सरकार ने पिछले करीब सीजन में भी सरकार करती रही और किसान खाद के लिए दर-दर भटकते रहे, यूरिया और डीएपी का स्टॉक डिमांड के आधा भी उपलब्ध नहीं कर पाई सरकार।

सरकार बिजली आपूर्ति में भेदभाव कर रही: ठाकुर

रायपुर। सरकारी विभागों एवं आम जनता को ईवी लेने की सलाह को हास्यपद करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ईंधन संकट के चलते सरकारी विभागों एवं आम जनता को ईवी लेने की सलाह दे रही है लेकिन बिजली उत्पादन को बढ़ाने के दिशा में कोई योजना नहीं बना रही है, ऐसे में सरकार की सलाह हास्यपद एवं जिम्मेदारी से भागना है। वर्तमान में जितना बिजली उत्पादन हो रहा है उतने



में शत-प्रतिशत घरों में पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रहा है। बिजली कटौती, लो वोल्टेज की गम्भीर समस्या से प्रदेश जूझ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 7 घंटा तो शहरी क्षेत्रों में 2 से 3 घण्टा बिजली बंद हो रही है। जनता परेशान है फिर सरकार इस प्रकार उलजुलूल सलाह क्यों दे रही है? प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश बिजली उत्पादन मामले में सरप्लस राज्य है फिर बिजली कटौती एवं लो वोल्टेज की समस्या क्यों है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिये? सोलर पैनल को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन अभी तक सोलर पैनल के बेहतर परिणाम नजर नहीं आ रहा है, सोलर से बिजली उत्पादन के दावे किए जा रहे हैं लेकिन बिजली कटौती, लो वोल्टेज पर बिजली विभाग मौन है।

जन सुविधा केंद्रों से किराया कमाने में लगी है सरकार: वर्मा

रायपुर। तिलदा नगर पालिका में गरीब, जरूरतमंद लोगों के उपयोग के लिए बनाएं गए आश्रय स्थल को 21 हजार रुपए महीने किराए पर व्यापारियों को दिया जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार का लक्ष्य केवल मुनाफाखोरी है। कमीशनखोरी के लालच में जन सुविधाओं के लिए किए गए निर्माण को भी व्यावसायिक उपयोग के लिए अपने चहेतों को



नियम विरुद्ध तरीके से दिया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है, पहले भी अंबिकापुर में संचालित सी मार्ट के भवन में प्रीमियम दारू दुकान खोलें, घुमका के गौठान और संडी के शमशान में शराब दुकान खोले गए अब तिलदा नगर पालिका में गरीबों के आश्रय स्थल में दुकानें खुलवा दी गईं। शासन की आश्रय स्थलों के निर्माण और संचालन की यह योजना किसी निजी किराएदारी या व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के लिए पैसों का लेनदेन करके इसे व्यापारियों को दे दिया गया है। जनता के पैसों से निर्मित जरूरतमंदों की सुविधा के लिए बनाए गए आश्रय स्थल को इस तरह से व्यावसायिक उपयोग के लिए सौंपना न केवल नियम विरुद्ध है बल्कि अनैतिक भी है।

बाल विवाह रोकने महिलाओं को किया गया जागरूक

रायपुर। प्रदेश में संचालित बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में लगातार जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में बाल विवाह रोकथाम, महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 21 मई को महिला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला के जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्डलाइन की संयुक्त टीम द्वारा वैभव संकुल संगठन दनगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को पॉक्सो एक्ट एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया गया कि बालिकाओं की वैधानिक विवाह आयु 18 वर्ष तथा बालकों की 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह किया जाना कानून मान्य है। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 एवं आपातकालीन सेवा 112 की जानकारी देते हुए किसी भी आपात स्थिति या बाल संरक्षण से जुड़ी समस्या की सूचना तत्काल देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही समाज से बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया।

लखपति दीदी अभियान को मिल रही नई गति बैगा अंचल के जंगलों की मिठास पहुँची बैंगलोर

रायपुर। जीपीएम जिले के सुदूर वनांचल और बैगा अंचल के ग्राम आमाडोब एवं केवंच की महिलाओं की मेहनत अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। जंगलों से संग्रहित प्राकृतिक शहद अब छत्तीसगढ़ की सीमाओं को पार कर देश के बड़े शहरों तक पहुँचने लगा है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहानु अंतर्गत गठित स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार शहद की पहली बड़ी खेप अब बैंगलोर भेजी गई है, जिससे ग्रामीण महिलाओं में उत्साह और आत्मविश्वास का नया संचार हुआ है। बैगा अंचल के घने जंगलों से



संग्रहित इस शुद्ध प्राकृतिक शहद की ब्रांडिंग एवं आकर्षक पैकेजिंग अरपा बिहान नाम से की जा रही है। यह कार्य तिपान महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा तैयार यह उत्पाद अब बाजार में अपनी गुणवत्ता और विशिष्टता के कारण अलग पहचान बना रहा है। बैंक्स मीटिंग में कलेक्टर ने

दिखाई हरी झंडी: जिला कलेक्टर डॉ. संतोष देवांगन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावटे ने बुधवार को अरपा सभा कक्ष में आयोजित बैंक्स मीटिंग के दौरान शहद की खेप को सकेतिक रूप से रवाना किया। इसके बाद तिपान महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा शहद बैंगलोर भेजा गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि यह

पहल न केवल स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार दिलाने का प्रयास है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहान योजना के माध्यम से जिले की महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं। जंगलों से प्राकृतिक संसाधनों का संग्रहण, उनकी वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और विपणन कर महिलाएं अब आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। राज्य सरकार उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर है और उन्हें व्यापक बाजार उपलब्ध करारक महिलाओं की आय में वृद्धि की जा सकती है।

स्तर तक बाजार उपलब्ध कराया जाए। बैगा अंचल के शहद का बैंगलोर तक पहुँचना इसी दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। **स्थानीय उत्पादों को मिलेगा ऑनलाइन बाजार** कलेक्टर ने जिला मिशन प्रबंधक को निर्देशित किया कि भविष्य में भी स्वसहायता समूहों के उत्पादों के राज्य से बाहर विपणन एवं ऑनलाइन विक्रय के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर है और उन्हें व्यापक बाजार उपलब्ध करारक महिलाओं की आय में वृद्धि की जा सकती है।

नीट पेपर लीक: आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय शिक्षामंत्री का मांगा इस्तीफा

रायपुर। नीट पेपर लीक मामले में आम आदमी पार्टी पार्टी द्वारा राजधानी रायपुर के अम्बेडकर चौक में प्रदर्शन कर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। आप नेताओं के कहा कि यह देश के 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला है। यह पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण और बड़े स्तर पर की गई मिलीभगत का परिणाम है। सवाल उठायो कि पिछले नीट पेपर लीक मामले में लिए जिम्मेदार लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई। ऐसे पेपर आमतौर पर लीक नहीं होते। इसका मतलब है कि इसमें बड़े पैमाने पर किसी तरह की



मिलीभगत है। इसमें राजनीतिक संरक्षण है। 2017,2021, 2024 और अब 2026 में पेपर लीक,ये अजुबा कैसे हो रहा है? सब मिले हुए हैं। 23 लाख से अधिक बच्चों ने पूरे साल रात-दिन जाग कर पढ़ाई की, और एक ही रात में उनका भविष्य खुलेआम बाजार में नीलाम हो गया। यह पहली बार नहीं है। पिछले 10 बरसों में 89 बार

प्रश्नपत्र लीक हुए-48 बार परीक्षा दोबारा हुई। हर बार वही वादे, और फिर वही चुप्पी। नीट-यूजी 2026 परीक्षा में कश्चित पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के सदमे के कारण देशभर में कई छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के दुखद मामले सामने आए हैं। इस घटनाक्रम ने छात्रों और उनके परिवारों के बीच भारी मानसिक तनाव और आक्रोश पैदा कर दिया है।